सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 101, नई दिल्ली । शुक्रवार, 20 जून 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सत्य बोलकर मित्र बनाना अच्छा है, परन्तु झूठ बेलकर मित्र बनाने से सत्य बोलकर शत्रु बनाना अधिक अच्छा है, क्योंकि आप संसार में सबको एक साथ प्रसन्न नहीं कर सकते।

03 भारत के प्रति अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का उदासीन रवैया
06 जीवित रहें पुस्तकालय
08 झारखंड में पेलोल पुल दो टुकड़े में बंटा, वाहनों की लम्बी काफिला जाम

बहुमुखी प्रतिभा की धनी नैन्सी बाटला सिंह

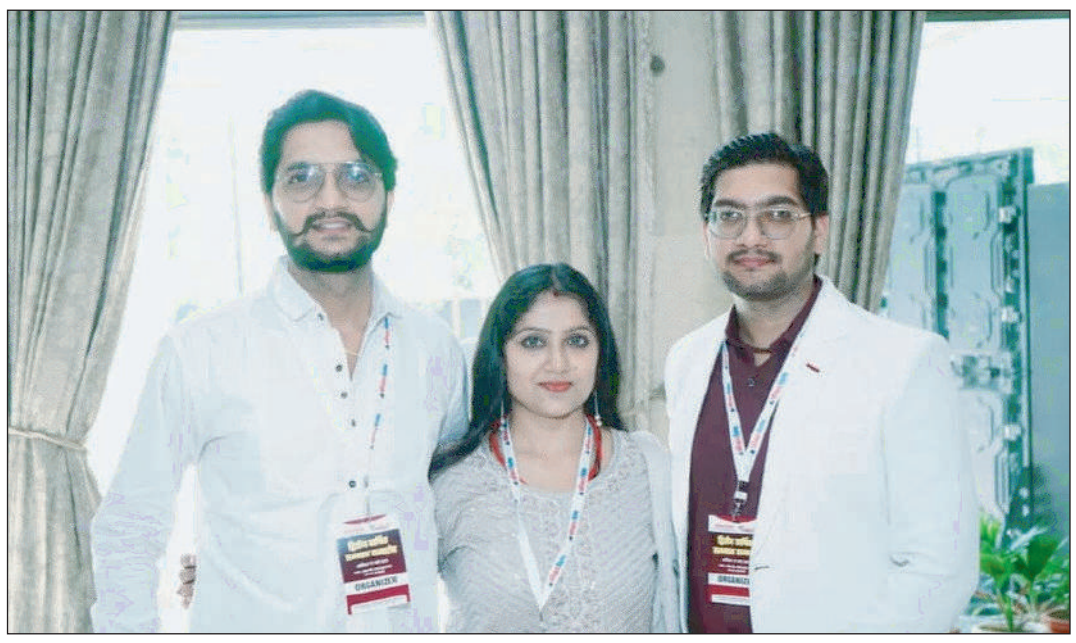

कर्म व उत्कंठा ने इन्हें नृत्य, योग, अंग्रेजी और रचनात्मक कलाओं की विस्तृत श्रृंखला जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, गायन, साहित्य, हाव-भाव, अभिव्यक्ति (मुख तथा हस्त मुद्राएं) और नाट्यकला सहित विभिन्न विषयों में युवा शिक्षार्थियों और बुजुर्गों दोनों को मार्गदर्शन करने का सौभाग्य दिया है।

प्रदर्शन कलाओं के प्रति इनके जज़बे ने इन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रेरित किया है - चाहे वह भजन हो, शायरी हो, नृत्य करना या नाट्य प्रदर्शन करना हो - दिल्ली के कुछ सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर, जिनमें मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम और प्यारे लाल भवन शामिल हैं। कलाओं से परे इन्हें प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है और हमारी प्यारी धरती माँ के वनस्पतियों और जीवों की सेवा और पोषण करने के हर अवसर का आनंद लेती हैं।

व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियाँः अपने कलात्मक प्रयासों के साथ-साथ, इन्होंने वित्त, कॉर्पोरेट के साथ-साथ प्रतिभूति बाजार में भी विशेषज्ञता हासिल की है। कंप्यूटर में इनकी दक्षता बुनियादी एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों से लेकर उन्नत एक्सेल और प्रोग्रामिंग भाषाओं तक फैली हुई है।

हाल ही में, इन्होंने ज्योतिष, अंकशास्त्र और वास्तु शास्त्र में रुचि विकसित कर जनता को सेवा प्रदान करनी शुरु करी है।

कृतज्ञताः सबसे बढ़कर इनके कहना है "मैं आज जो भी हूँ, उसके लिए मैं अपने माता-पिता की आभारी हूँ, जिनके प्यार और समर्थन ने मेरी यात्रा को यह आकार प्रदान किया है।"

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे का आठ किलोमीटर का हिस्सा इस दिन से होगा शुरू, नोएडा-फरीदाबाद का सफर होगा आसान

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रसवे का डीएनडी-मीठापुर खंड अगले मार्च में खुलेगा जिससे नोएडा-फरीदाबाद यात्रा आसान होगी। फरीदाबाद जाने वाले मथुरा रोड से बचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। मेट्रो लाइन के ऊपर एलिवेटेड रोड बन रहा है। बदरपुर में इको-पार्क और अन्य विकास कार्य दक्षिणी दिल्ली को लाभान्वित करेंगे और यातायात कम करेंगे।

संजय बाटला

नई दिल्ली। नोएडा से फरीदाबाद जाने वाले लोगों के लिए राहत वाली खबर है। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे के डीएनडी से मीठापुर चौक तक आठ किलोमीटर के हिस्से को अगले साल मार्च में शुरू कर दिया जाएगा। इसके शुरू होने से फरीदाबाद जाने वाले वाहन चालकों को मथुरा रोड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वह डीएनडी से सीधे एक्सप्रसे वे का इस्तेमाल कर अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा।

दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का 24 किलोमीटर लंबा हिस्सा खोला गया था। यह दिल्ली के मीठापुर से फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक का था। इसका डीएनडी से मीठापुर का हिस्सा शुरू नहीं हुआ है।

भाजपा सांसद ने बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता में कहा कि आठ किलोमीटर के इस हिस्से को अगले साल मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। एक्सप्रेस वे का ये हिस्सा शुरू न होने की वजह से नोएडा डीएनडी से फरीदाबाद जाने वाले वाहन चालक मथुरा रोड का इस्तेमाल करते हैं।

इससे मथुरा रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। यहां सुबह व शाम को भयंकर जाम लगता है। जब इस शेष हिस्से को शुरू कर दिया जाएगा तो फरीदाबाद जाने वाले वाहन चालक सीधे डीएनडी से एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल कर सकेंगे।

मेट्रो लाइन के ऊपर से बनाया जा रहा एलिवेटेड

डीएनडी से मीठापुर चौक तक के हिस्से में कई जगहों पर मेट्रो लाइन बीच में आ रही थी। इस वजह से इस हिस्से का काम शुरू करने में अड़चन आ रही थी। अब पिलर बनाकर मजेंटा मेट्रो लाइन के ऊपर से एलिवेटेड बनाया जा रहा है। इसके बनने से सराय काले खां से फरीदाबाद जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। वह सराय काले खां से एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल कर सकेंगे।

केंद्र सरकार से सबसे ज्यादा लाभ दक्षिणी दिल्ली को मिला

सांसद बिधूड़ी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने देश के हर कोने तक विकास का लाभ पहुंचा है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। केंद्र की भाजपा सरकार में दक्षिण दिल्ली को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। दिल्ली से बडोदरा का नेशनल हाईवे दक्षिण दिल्ली की लाइफ लाइन बनने जा रहा है।

बदरपुर से होकर जाने वाले 6 लेन के इस नए हाईवे का 7000 करोड़ की लागत से निर्माण चल रहा है, मीठापुर चौक पर फ्लाई ओवर का निर्माण, मीठापुर चौक के निकट आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल पर नए पुलों के निर्माण से दक्षिण दिल्ली से गुजरने वाली जनता को बड़ी राहत मिली है।

बदरपुर में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा

दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए बदरपुर में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा शिव मूर्ति-महिपालपुर (द्वारका एक्सप्रेसवे) और नेल्सन मंडेला रोड के बीच पांच किलोमीटर लंबी सुरंग रंगपुरी, धौला कुआं, राव तुला राम मार्ग और एनएच-48 पर यातायात की भीड़ को काफी हद तक कम कर देगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 100 दिन में ही कामकाज के कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। इस मौके पर भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, महरौली जिला भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी, दक्षिण जिला भाजपा की अध्यक्ष माया बिष्ट और विधायक करतार सिंह तंवर, गजेंद्र यादव, और श्री चंदन चौधरी भी उपस्थित रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने द्वितीय व चौथे शनिवार की सभी कोर्टो की छुट्टी को किया निरस्त, अब जुलाई 2025 से महीने के सभी शनिवार को खुलेंगी अदालतें

SUPREME COURT OF INDIA

Date: 16th June, 2025

NOTICE

In exercise of the powers conferred by Article 145 of the Constitution and all other enabling provisions in this behalf, the Supreme Court, with the approval of the President, has amended Rules 1, 2 and 3 of Order II of the Supreme Court Rules, 2013, which shall take effect from 14th July, 2025.

Consequent upon the amendment, the sentence occurring at Serial No.2 in the Calendar, 2025, "Registry will remain closed on 2nd and 4th Saturdays of each month." shall stand deleted.

Sd/-
[Kuntal Sharma Pathak]
OSD(Registrar) (Court & Building)

अपने फायर एक्स्टिंग्यूशर को जानें - सुरक्षा जागरूकता के साथ शुरू होती है!

हर आग अलग होती है - और इसी तरह हर आग बुझाने वाला भी। गलत का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। जाने त्वरित गाइड क्या कहते हैः

1. पानी (लाल लेबल) - कक्षा ए के लिए आग (लकड़ी, कागज, कपड़ा)
2. फोम (क्रीम लेबल) - कक्षा ए और बी फायर के लिए (ज्वलित तरल पदार्थ)
3. सूखा पाउडर (नीला लेबल) - बहु-उद्देश्य; कक्षा ए, बी, सी के लिए
4. (CO2 (ब्लैक लेबल) - बिजली की आग और ज्वलनशील तरल पदार्थ के लिए
5. गीला केमिकल (पीला लेबल) - रसोई की आग के लिए (कक्षा पन्नी, वसा)

A. उपयोग करने से पहले हमेशा लेबल की जाँच करें!

B. बिजली या तेल की आग पर कभी पानी का उपयोग न करें!

C. अग्नि सुरक्षा सही ज्ञान और सही उपकरणों से शुरू होती है। सतर्क रहें। सुरक्षित रहें।

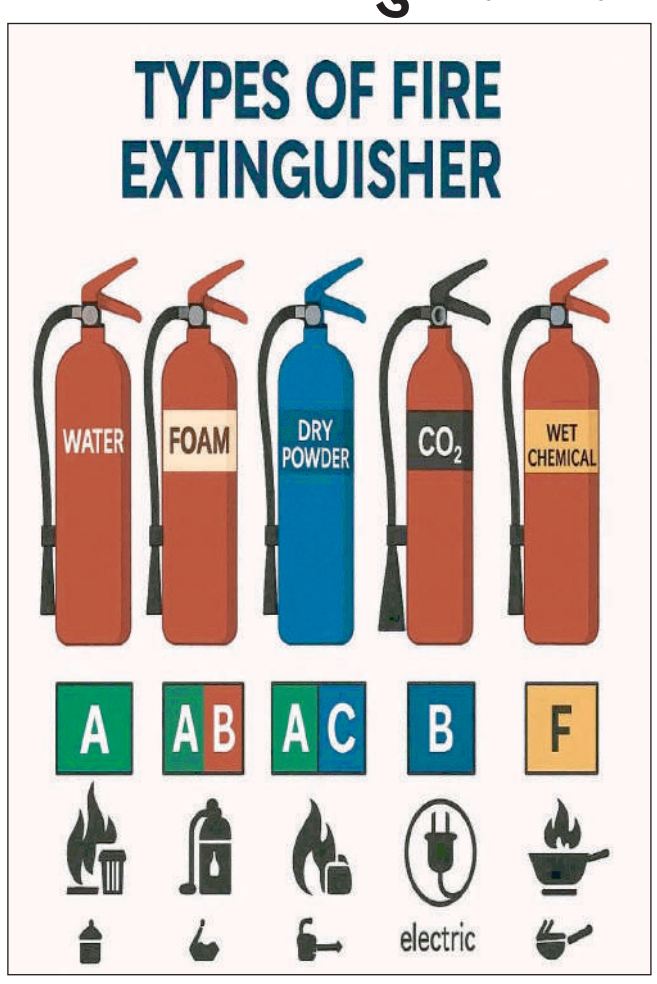

पार्यावरण पाठशाला : "बनाएं छोटे ग्रीन बडीज़" — प्रकृति रक्षकों की नई पीढ़ी

✍ डॉ. अंकुर शरण

आज के इस बदलते युग में जहाँ टेक्नोलॉजी और विकास की रफ्तार दिन-प्रतिदिन तेज़ हो रही है, वहीं प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की ज़िम्मेदारी और भी अहम होती जा रही है। ऐसे में हमें एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो सिर्फ पढ़ाई में होशियार ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण रक्षक भी हो। इसी उद्देश्य को लेकर रपार्यावरण पाठशालार की ओर से एक अभिनव पहल — रग्रीन बडीज़ बनाएंर — शुरू की जा रही है।

कौन हैं ये ग्रीन बडीज़?

ग्रीन बडीज़ वो नन्हें-मुन्ने बच्चे हैं जो अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा को अपनी ज़िम्मेदारी मानते हैं। ये बच्चे ना केवल जागरूक हैं बल्कि अपने प्रयासों से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के Nature Protector बनते हैं जैसे:

Water Saviour – जल रक्षक

इन बच्चों को पानी के महत्व और उसके संरक्षण की जानकारी दी जाती है। वे सीखते हैं कि बर्बादी नहीं, बचत करें — जैसे टपकते नलों को बंद करना, ब्रश करते समय पानी बंद रखना, वर्षा जल संचयन के तरीके अपनाना आदि।

Park Saviour – पार्क रक्षक

ये छोटे ग्रीन बडीज़ अपने मोहल्ले के पार्कों को स्वच्छ और हरा-भरा बनाए रखने में अग्रणी होते हैं। वे पेड़ों को पानी देना, सूखे पत्तों को इकट्ठा कर कम्पोस्ट बनाना और पार्क में कूड़ा ना फेंकने की सलाह दूसरों को देना सीखते हैं।

Animal Welfare Buddy – पशु कल्याण सहयोगी

ये बच्चे जानवरों के प्रति करुणा और संवेदना रखना सीखते हैं। वे सड़कों पर घायल या भूखे जानवरों को खाना खिलाना, पशु-पक्षियों के लिए जल पात्र रखना, और पालतू जानवरों की देखभाल के सही तरीके जानना सीखते हैं।

Tree Planter – वृक्ष मित्र

हर बच्चा एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे — यह मंत्र ग्रीन बडीज़ का मूल उद्देश्य है। पेड़ों की पहचान, उनके लाभ और नियमित देखभाल को इनकी जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाता है।

Cleanliness & Anti-Plastic Buddy – सफाई योद्धा

साफ-सफाई का संदेश फैलाना, प्लास्टिक का बहिष्कार करना और रीसायक्लिंग की आदत डालना इन्हें विशेष बनाता है। ये बच्चे समाज को यह सिखाते हैं कि हर छोटा प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है।

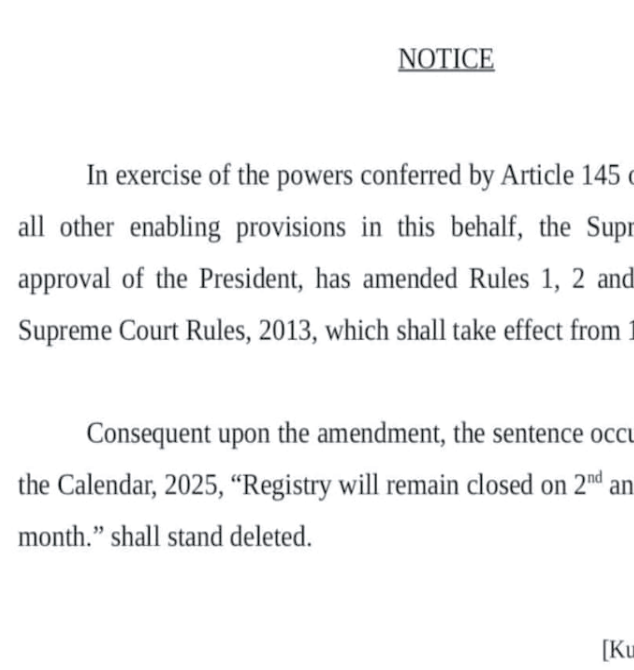

हमारा उद्देश्य

रपार्यावरण पाठशालार के अंतर्गत ग्रीन बडीज़ न केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि कार्यशालाओं, नेचर वॉक, पक्षी अवलोकन, पौधारोपण, और कूड़ा प्रबंधन जैसे प्रायोगिक कार्यों के ज़रिए अनुभव भी प्राप्त करेंगे।

यह कार्यक्रम स्कूलों, सोसाइटीज़, और आरडब्ल्यूए (RWA) के सहयोग से चलाया जाएगा, जहाँ बच्चों को 'ग्रीन बडी किट्स', बैज, प्रमाणपत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे।

आइए, एक नई शुरुआत करें

आइए, हम सब मिलकर इस आंदोलन का हिस्सा बनें और अपनी अगली पीढ़ी को रप्रकृति रक्षकर के रूप में तैयार करें। हर बच्चा एक ग्रीन बडी बने, यही रपार्यावरण पाठशालार का लक्ष्य है।

क्योंकि प्रकृति बचाओगे तो भविष्य बचाओगे!

रछोटे कदम, बड़ा बदलाव!र

अगर आप भी अपने बच्चों को ग्रीन बडी बनाना चाहते हैं या स्कूल, सोसाइटी में यह पहल शुरू करना चाहते हैं, तो हमें संपर्क करें।

संपर्कः
[indiangreenbuddy@gmail.com]

एक पहल — भारतीय ग्रीन बडी और पार्यावरण पाठशाला के साथ।

indiangreenbuddy@gmail.com

प्रकाशनार्थ : बदहाल मनरेगा : रोजगार नहीं, निराशा की गारंटी (आलेख : डॉ. विक्रम सिंह)

पिछले दिनों मीडिया में छपी खबरों के अनुसार, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत खर्च पर कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं। 10 जून को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए मनरेगा के तहत खर्च को अपने वार्षिक आवंटन के 60 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। सरकार का यह निर्णय मनरेगा की मूल अवधारणा के खिलाफ है।

मनरेगा की मूल अवधारणा की अवहेलना

मनरेगा एक मांग-आधारित योजना है, जिसमें कोई भी बेरोजगार व्यक्ति काम माँग सकता है। जितने मजदूर काम माँगेंगे, उतना काम देना होगा। इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, जब तक कि एक परिवार 100 दिन का रोजगार पूरा न कर ले। मांग के आधार पर काम देना मनरेगा की मूल भावना है। यह काम मजदूर वित्तीय वर्ष के किसी भी महीने में माँग सकता है। मनरेगा कानून के अनुसार, इसमें कोई भी रुकावट मजदूरों के काम के कानूनी अधिकार के खिलाफ है।

इसी अवधारणा के चलते मनरेगा को वित्त मंत्रालय के सरकारी खर्च को नियंत्रित करने वाले नियमों से बाहर रखा गया था। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2017 में मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना लागू की थी, जिसका तथाकथित मकसद मंत्रालयों को नकदी प्रवाह प्रबंधन और अनावश्यक उधारी से बचाने में मदद करना था।

अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली मनरेगा को इसके दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का तर्क था कि यह एक मांग-आधारित योजना है, जिस पर खर्च की निश्चित सीमा तय करना व्यवहारिक नहीं है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है कि मनरेगा को भी मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना के ढाँचे के अंतर्गत लाया जाए।

केंद्र सरकार की नीति और 'रोजगार के अधिकार' पर हमला

हालांकि, भाजपा-नीत केंद्र सरकार के इस फैसले से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कोई इकलौता फैसला नहीं है, जो न केवल ग्रामीण भारत में रोजगार प्रदान करने वाली मनरेगा को कमजोर करेगा, बल्कि इसके तहत 'रोजगार के अधिकार' के भी खिलाफ है।

बजट में लगातार कटौती से लेकर भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर नित नई जटिलताएँ पैदा करने वाली तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग -- ये सभी कदम मनरेगा के मौलिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाले हैं। मोदी सरकार अपने इन कदमों से न केवल विभिन्न अध्ययनों द्वारा सिद्ध मनरेगा की उपयोगिता को अनदेखा करती है, बल्कि ग्रामीण आर्थिक संकट और बेरोजगारी की गंभीर समस्या से निपटने में अपनी उदासीनता भी दर्शाती है।

यदि उपरोक्त निर्णय लागू होता है, तो इसका मतलब है कि इस वर्ष सितंबर के अंत तक इस योजना के लिए बजट आवंटन (86,000 करोड़ रुपये) का 60 प्रतिशत, यानी केवल 51,600 करोड़ रुपये ही उपलब्ध होंगे। यह मनरेगा के तहत रोजगार सृजन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा, 21,000 करोड़ रुपये, पिछले वित्तीय वर्ष की लंबित देनदारियों के भुगतान में खर्च हो चुका है। इस तरह के फैसले से जमीनी स्तर पर मांग के बावजूद मजदूरों को मनरेगा में काम के लिए विभिन्न तरीकों से हतोत्साहित किया जाएगा।

अधिकांश समस्याओं का मूल कारण अपर्याप्त बजट

दरअसल, मनरेगा को कमजोर करने का सबसे बड़ा कारण लगातार बजट में कमी और समय पर आबंटन का राज्यों तक न पहुँचना है। इससे सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

हालांकि, हमारी वित्त मंत्री समय-समय पर मीडिया में दावा करती रहती हैं कि मनरेगा के लिए धन की कोई कमी नहीं है और काम की मांग के अनुसार इसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन यह दावा सच्चाई से कोसों दूर है। धन की कमी के चलते ही अघोषित रूप से काम की मांग को नियंत्रित किया जाता है। विभिन्न तरीकों से मजदूरों को हतोत्साहित किया जाता है। यह बात सरकार की संसदीय समिति की 2024 की एक रिपोर्ट में भी एक बड़ी कमजोरी के रूप में चिह्नित की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'आवश्यकता के आधार पर संसाधनों की पूर्ति की जा सकती है,' लेकिन वर्ष की शुरुआत में अनुमानित बजट में ही धन की कटौती करने से मनरेगा के कार्यान्वयन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, समिति ने जमीनी स्तर पर इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए धन की कमी को एक बहुत बड़ी बाधा माना है। मनरेगा के लिए शुरू में ही उपयुक्त बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसका आधार पिछले वर्ष के खर्च का रुझान हो सकता है।

गौरतलब है कि पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी सहित देश के कई अर्थशास्त्रियों ने मनरेगा के लिए प्रति वर्ष कम से कम 2.64 लाख करोड़ रुपये का बजट आबंटन सुझाया है। यहाँ तक कि विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इस कार्यक्रम के लिए देश की जीडीपी का कम से कम 1.7% आबंटित किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, वर्ष 2024-25 में मनरेगा के लिए किया गया आबंटन जीडीपी का मात्र 0.26% है। इस वर्ष के बजट (2025-26) में भी केवल 86,000 करोड़ रुपये ही मनरेगा के लिए रखे गए हैं। यह योजना की व्यापक आवश्यकताओं और ग्रामीण भारत की बढ़ती आर्थिक असुरक्षा के संदर्भ में बेहद अपर्याप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में ग्रामीण गरीबों की आजीविका की सुरक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है।

इसी तरह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने 22 मई को संसद में प्रस्तुत अपनी आठवीं रिपोर्ट में उजागर किया कि मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान में देरी अब भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह देरी उन ग्रामीण मजदूरों को प्रभावित कर रही है, जो अपनी आजीविका के लिए इस योजना पर निर्भर हैं। सरकार संसद की ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति द्वारा लगातार दिए गए सुझावों को अनदेखा करती आ रही है, लेकिन मनरेगा को कमजोर करने वाले सुझावों को तत्परता से लागू करती है।

मजदूरी दरों की गणना में विसंगतियाँ

इसी तरह, संसद की ग्रामीण विकास पर गठित एक समिति ने मनरेगा के तहत मजदूरी को कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन करने की सिफारिश की है। इस समिति का मानना है कि वर्तमान दरें दैनिक बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त हैं, और एक न्यायसंगत मजदूरी के बिना यह योजना ग्रामीण मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्य में विफल हो रही है।

इस वर्ष मार्च में संसद में पेश की गई रिपोर्ट में भी समिति ने सिफारिश की कि ग्रामीण मजदूरी पर महंगाई के वास्तविक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मजदूरी दरों में संशोधन किया जाए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जो यह समिति लंबे समय से उठाती आ रही है, वह है मनरेगा के तहत मजदूरी दरों की गणना के विसंगतिपूर्ण तरीके।

दरअसल, मनरेगा के तहत मजदूरी दरों की गणना खेत मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। अभी तक इसके लिए 1 अप्रैल 2009 की मूल दरों को आधार बनाकर संशोधन किया जाता है। संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस पद्धति की तीव्र आलोचना करते हुए कहा है कि "2009-10 को आधार वर्ष मानकर की जा रही गणना अब अप्रासंगिक और निष्प्रभावी हो चुकी है, जो मौजूदा महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप कोई उचित आँकड़ा देने में असमर्थ है।"

इससे पहले, महेंद्र देव समिति ने भी यही तर्क दिया था और सुझाव दिया था कि मनरेगा मजदूरी सूचकांक का आधार वर्ष 2014 होना चाहिए। स्थायी समिति ने अपनी अनुशंसा में स्पष्ट रूप से कहा था कि "कम मजदूरी दरों की समस्या का समाधान संभवतः आधार वर्ष और मूल दरों की समय के अनुरूप पुनर्समीक्षा तथा उनके यथोचित बढ़ोतरी के माध्यम से किया जा सकता है।"

अनूप सतपथी समिति ने भी सुझाव दिया था कि मनरेगा के तहत मजदूरों को प्रतिदिन न्यूनतम 375 रुपये की मजदूरी दी जानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने संसद की अपनी ही स्थायी समिति की इस सिफारिश को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे उसकी मंशा स्पष्ट झलकती है।

इस वर्ष भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा की मजदूरी दरों में केवल 2% से 7% तक की मामूली वृद्धि की गई है। कम मजदूरी दर मजदूरों को इस योजना में भाग लेने से हतोत्साहित करती है, जिससे ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने के इसके मूल उद्देश्य को ही कमजोर किया जा रहा है।

मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि केवल आर्थिक आवश्यकता का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और ग्रामीण सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कम मजदूरी न केवल इस योजना की प्रभावशीलता को सीमित करती है, बल्कि ग्रामीण जनता को गरीबी, शोषण और पिछड़ेपन की चपेट में भी बनाए रखती है।

यदि मनरेगा की मजदूरी को महंगाई दर, न्यूनतम वेतन मानकों, और वास्तविक जीवन-यापन की लागत के अनुरूप तय किया जाए, तो यह योजना भारत की ग्रामीण आबादी के लिए एक प्रभावशाली परिवर्तनकारी साधन बन सकती है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी, मजदूरी के अधिकार को मजबूती मिलेगी और मजदूरों की गरिमा में भी वृद्धि होगी। यह उपेक्षा न केवल योजना की प्रभावशीलता को कमजोर करती है, बल्कि देश के करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों और गरिमा के साथ भी अन्याय करती है।

मनरेगा में कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाने की जरूरत

संसदीय समिति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 किया जाए। यह लंबे समय से चली आ रही मांग है, लेकिन अभी तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी होने के बावजूद प्रति वर्ष काम के दिन औसतन 50 दिन प्रति परिवार से अधिक नहीं हो पाते। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा के तहत प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस केवल 50.18 ही रहे, और कुल पंजीकृत परिवारों में से केवल 7% परिवारों को ही वादा किए गए 100 दिनों का रोजगार मिल पाया।

वर्तमान में मनरेगा में कुल 15.33 करोड़ परिवारों के जॉब कार्ड बने हैं, जिनमें 26.39 करोड़ मजदूर पंजीकृत हैं। इनमें से 8.41 करोड़ सक्रिय जॉब कार्ड हैं, जिनमें 11.98 करोड़ मजदूर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष मनरेगा के तहत कुल कार्य दिवसों में 7.1 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2023-24 में कुल 288.83 करोड़ कार्यदिवस काम हुए थे, जो वर्ष 2024-25 में केवल 268.44 करोड़ रह गए।

पश्चिम बंगाल में मनरेगा का संकट

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत पंजीकृत 2.56 करोड़ मजदूर, जिनके पास जॉब कार्ड हैं और जो अकुशल मजदूरी के लिए पूर्णतः पात्र हैं, पिछले तीन वर्षों से काम से वंचित हैं। इन मजदूरों को 'काम के कानूनी अधिकार' (मनरेगा के तहत काम पाने का अधिकार) से भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण वंचित रखा जा रहा है।

हालांकि, यह सत्य है कि देश के अधिकांश राज्यों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, मनरेगा के कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके पीछे ठेकेदारों, स्थानीय नेताओं (जिनमें अधिकांश सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े हैं), और विभिन्न स्तरों की नौकरशाही के बीच साँठगाँठ जिम्मेदार है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन मजदूरों का इस भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों से दंडित किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सबसे पहली आवश्यकता मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की होती है, जो न तो केंद्र सरकार में दिखाई देती है और न ही पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में। केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से हल करने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए भ्रष्टाचार के नाम पर टीएमसी सरकार को निशाना बना रही है। वहीं, टीएमसी सरकार खुद को पीड़ित बताकर ग्रामीण गरीबों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। इन दोनों सरकारों की प्राथमिकता भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं है।

परिणामस्वरूप, सबसे अधिक पीड़ित वे मेहनतकश मजदूर हैं, जो न तो भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं और न ही इसके पक्षधर, लेकिन उन्हें अपने कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने मनरेगा, 2005 की धारा 27 का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल में योजना के लिए वित्तीय सहायता रोक दी। यह धारा योजना के कार्यान्वयन में नियमों के उल्लंघन की स्थिति में धनराशि रोकने का अधिकार देती है।

गुजरात में मनरेगा घोटाला : भाजपा का दोहरा मापदंड

पिछले कुछ दिनों में भाजपा की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मॉडल की पोल देश की जनता के सामने खुल गई है। लड़ाई तो दूर की बात है, भाजपा के नेता भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वैसे तो देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नवउदारवादी नीतियों का चरम है, जिसके चलते देश के संसाधन शासक वर्ग के कुछ कॉर्पोरेट घरानों और विदेशी पूँजी को सौंपे जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में भाजपा के विकास मॉडल के रूप में प्रचारित गुजरात में मनरेगा में कई सौ करोड़ रुपये के घोटाले उजागर हुए हैं।

ऐसे ही एक मामले में गुजरात के दाहोद जिले में राज्य के पंचायत और कृषि मंत्री बचू खाबड़ के बेटे बलवंत खाबड़ को दाहोद पुलिस ने मनरेगा में 70 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक खुलासों में सामने आया है कि यह घोटाला पूरी तरह फर्जी नेटवर्क पर आधारित था, जिसमें सड़कों, बाँधों, और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों को केवल कागजों पर दिखाया गया।

मनरेगा के तहत आदिवासी समुदायों के लिए नियोजित रोजगार से जुड़ी धनराशि को कथित रूप से जाली दस्तावेजों के माध्यम से हड़प लिया गया और उसे उन एजेंसियों को भेजा गया, जिनका संबंध मंत्री के बेटों से था। इस घोटाले में मंत्री बचू खाबड़ के दोनों बेटों, बलवंत और किरण, शामिल पाए गए हैं।

पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकारों की वास्तविक मंशा को समझने के लिए यह जरूरी है कि सोशल ऑडिट की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाए। इस क्षेत्र में सोशल ऑडिट एक अहम उपकरण है, जो कार्यों की सामाजिक निगरानी सुनिश्चित करता है। इसकी रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

हालांकि, जो सरकारें और राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की दहाड़ करती हैं, वे अक्सर खुद सोशल ऑडिट से बचती नजर आती हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं में पारदर्शिता लाने वाला यह तंत्र उनके लिए असहज होता है। सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों को डराना-धमकाना, उनके खिलाफ हिंसा और झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव डालना आम हो गया है।

पिछले दशक में भाजपा सरकार का मनरेगा को लागू करने का रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है। यह स्पष्ट रूप से मनरेगा की मूल भावना पर सरकार के निरंतर हमलों को दर्शाता है। मनरेगा को लगातार कमजोर करना भारत के मेहनतकश लोगों के अर्जित रोजगार के अधिकार पर एक संगठित हमला है।

(डॉ. विक्रम सिंह अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव हैं)

इस दुनिया में सबसे बड़ी कला है, हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना।

जहां चार बर्तन होते हैं वहां आवाज़ तो होगी ही, इसलिए प्रत्येक से कभी न कभी प्रेम/द्वेष बना ही रहता है। यदि दो लोगों में कभी लड़ाई ना हुई हो तो समझ लेना, रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। इसलिये ऐसे लोगों से सदा संभल के रहना चाहिए जिनके दिल में भी 'दिमाग' होता है। ध्यान रहे कि जीवन ऐसा नहीं है कि हम जैसा सोचें, सब वैसा ही हो जाए। यदि ऐसा हो जाए तो ज़िंदगी और सपने में अंतर ही क्या रह जाएगा? एक बात हमेशा याद रखने जैसी है यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीजें, ना रिश्ते, ना दुःख और ना ही जीवन। यहां हर आती सांस अंतिम हो सकती है, इसलिए हर आती हुई सांस के साथ 'धन्यवाद' और हर जाती हुई सांस के साथ 'आभार' का भाव जागता रहे।

मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति को छूना क्यों नहीं चाहिए?

इसके कई कारण हैं।

मुख्यतः, यह माना जाता है कि मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा के बाद पवित्र माना जाता है और उन्हें छूने से उनकी पवित्रता भंग हो सकती है। इसके अतिरिक्त, भक्त हमेशा अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध नहीं हो सकते हैं, और इसलिए मूर्तियों को छूने से बचना चाहिए।

मंदिर में मूर्तियों को न छूने के कुछ और कारण हैं:

शुद्धता:

हिंदू धर्म में, किसी भी धार्मिक कर्मकांड से पहले शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता है। यदि कोई भक्त शुद्ध मन और शरीर से मंदिर में प्रवेश नहीं करता है, तो उसे मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए।

श्रृंगार:

कुछ मूर्तियों, जैसे शिवलिंग, को चंदन और भस्म से सजाया जाता है। यदि कोई अन्य मूर्ति को छूता है, तो उस पर भी चंदन लग सकता है, जो उचित नहीं है।

श्रृंगार का बिगड़ना:

सुबह के समय मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता है, और यदि उन्हें छुआ जाए तो उनका श्रृंगार बिगड़ सकता है। इसलिए, मूर्तियों को छूने से बचना चाहिए।

गर्भगृह:

मूर्तियां आमतौर पर गर्भगृह के अंदर रखी जाती हैं, जिसे आम भक्त नहीं छू सकते।

भक्ति और सम्मान:

भगवान की मूर्ति को छूना एक पवित्र कार्य है, और इसे केवल पुजारी या विशेष भक्त ही कर सकते हैं।

नकारात्मक ऊर्जा:

कुछ लोगों का मानना है कि मूर्तियों को छूने से नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, खासकर यदि व्यक्ति शुद्ध न हो।

मंदिर की हर एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके बाद ही उसकी पूजा का विधान है। ऐसे में यदि हम मंदिर के भीतर प्रवेश करने के बाद मूर्तियों का स्पर्श करते हैं तो उनकी पवित्रता कम हो सकती है।

कुंडलिनी-योग तथा तांत्रिक परंपरा में प्रत्येक चक्र (ऊर्जा केंद्र) की अधिष्ठात्री (प्रवर्तक) देवी-शक्तियों के हैं। साधारणतः पाँच मुख्य चक्रों से सम्बंधित पाँच प्रमुख योगिनी मानी जाती हैं:

1. राकिनी (ऋकिणी)

● चक्रः स्वाधिष्ठान (दूसरा चक्र, नाभि के ठीक नीचे)

● रूप-स्वभावः जल तत्व से सम्बन्धित, आम तौर पर केसरिया या सुनहरे रंग की, चार हाथों वाली, कदली-फूल (केले के फूल) धारण किए हुए

2. लाकिनी (लकीणी)

● चक्रः मणिपूर (तीसरा चक्र, नाभि के ऊपर)

● रूप-स्वभावः अग्नि तत्त्व से जुड़ी, पीली या सुनहरी, चार हाथों में अग्नि-चिन्हक करोड़, मोती तथा रोली (लाल सुपारी) धारण करती हुई

3. काकिनी (काकिणी)

● चक्रः अनाहत (चौथा चक्र, हृदयस्थल)

● रूप-स्वभावः वायु तत्त्व की देवी, सफेद या हल्की गुलाबी रंग की, चार हाथों में गदा, कमल, धनुष-बाण तथा रुद्राक्ष-माला धारण करती

4. शाकिनी (शकिणी)

● चक्रः विशुद्धि (पाँचवाँ चक्र, गले के पास)

● रूप-स्वभावः आकाश (वाक्) तत्त्व से संबंधित, हल्के नीले या सफेद रंग की, चार हाथों में शंख, चक्र, कमल और त्रिशूल रखती हुई

5. हाकिनी (हकिणी)

● चक्रः आज्ञा (छठा चक्र, मध्याक्षी बीच)

● रूप-स्वभावः चित्त (मनोबुद्धि) तत्त्व की देवी,ellikle तांबे या फीके सफेद रंग की, छः या आठ हाथों में जपमाला, त्रिपुंड (तीन-horizontal tilak), शंख-शिवलिंग आदि धारण करती

इनके महत्व की संक्षिप्त व्याख्या

● चक्राधिष्ठात्री शक्तियाँः कुंडलिनी-योग में प्रत्येक चक्र का संचालन और जागृति इनके माध्यम से माना जाता है। जैसे राकिनी स्वाधिष्ठान में काम (इच्छा), आनन्द और रचनात्मक ऊर्जा को संतुलित करती है, वैसे ही हाकिनी आज्ञाचक्र में एकाग्र चित्त व विवेक-बुद्धि को स्थिर करती है।

● तत्त्व-विकासः प्रत्येक देवी किसी-न-किसी पाँच तत्व (भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश) या मानस तत्त्व से जुड़ी होती है। साधना (ध्यान, मंत्र-जप, आसन, प्राणायाम) के माध्यम से इनकी कृपा से शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक ऊँचाई प्राप्त होती है।

● साधना पद्धतिः पारंपरिक रेकी, कुंडलिनी प्राणायाम, ध्यान मंत्र (जैसे "ॐ हाँ ह्रीं हाँ उँ जलानि स्वाहा"– शाकिनी मंत्र) आदि माध्यमों से इन देवी-शक्तियों का आह्वान किया जाता है। इससे चक्रों में अवरोध दूर होकर ऊर्जा सुचारू प्रवाहित होती है।

> निष्कर्षः

● राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी और हाकिनी — ये सभी तांत्रिक सिद्धियों में प्रचलित चक्राधिष्ठात्री योगिनियाँ हैं। इनके ध्यान, साधना और मंत्रों के द्वारा साधक अपने चक्रों में ऊर्जा जागृत करके आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकता है।

क्या होतें हैं पंचक?

क्या पंचक में कर सकते हैं शुभ कार्य

==========

हिन्दू पंचांग अनुसार प्रत्येक माह में पांच ऐसे दिन आते हैं जिनका अलग ही महत्व होता है। प्रचलित मान्यता अनुसार पंचक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। प्रत्येक माह का पंचक अलग अलग होता है तो किसी माह में शुभ कार्य नहीं किया जाता है तो किसी माह में किया जाता है।

पंचक क्या है?

==========

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चन्द्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चन्द्र ग्रह का कुम्भ और मीन राशी में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है। अर्थात पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को 'पंचक' कहा जाता है।

अगर आधुनिक खगोल विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 360 अंशों वाले भचक्र में पृथ्वी जब 300 अंश से 360 अंश के मध्य भ्रमण कर रही होती है तो उस अवधि में धरती पर चन्द्रमा का प्रभाव अत्यधिक होता है। उसी अवधि को पंचक काल कहते हैं।

पंचक में नहीं करते हैं ये पांच कार्य:

==========

शास्त्रों में निम्नलिखित पांच कार्य ऐसे बताए गए है जिन्हें पंचक काल के दोरान नहीं किया जाना चाहिए। जैसे 1.लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, 2. मकान पर छत डलवाना, 3. शव जलाना, 4. पलंग या चारपाई बनवाना और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना।

यदि लकड़ी खरीदना अनिवार्य हो तो पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता के नाम का हवन कराएं। यदि मकान पर छत डलवाना अनिवार्य हो तो मजदूरों को मिठाई खिलने के पश्चात ही छत डलवाने का कार्य करें। यदि पंचक काल में शव दाह करना अनिवार्य हो तो शव दाह करते समय पांच अलग पुतले बनाकर उन्हें भी आवश्य जलाएं।

इसी तरह यदि पंचक काल में पलंग या चारपाई लाना जरूरी हो तो पंचक काल की समाप्ति के पश्चात ही इस पलंग या चारपाई का प्रयोग करें। अंत में यह कि यदि पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करना अनिवार्य हो तो हनुमान मंदिर में फल चढ़ाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो जाता है।

पंचक के प्रकार जानिए:

==========

1.रविवार को पड़ने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है।

2.सोमवार को पड़ने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है।

3.मंगलवार को पड़ने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है।

4.शुक्रवार को पड़ने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है।

5.शनिवार को पड़ने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है।

6.इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को पड़ने वाले पंचक में ऊपर दी गई बातों का पालन करना जरूरी नहीं माना गया है। इन दो दिनों में पड़ने वाले दिनों में पंचक के पांच कामों के अलावा किसी भी तरह के शुभ काम किए जा सकते हैं।

पंचक के नक्षत्रों का प्रभाव:-

==========

1. धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है।

2. शतभिषा नक्षत्र में कलह होने की संभावना रहती है।

3. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना रहती है।

4. उतरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है।

5. रेवती नक्षत्र में धन हानि की संभावना रहती है।

भारत के प्रति अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का उदासीन रवैया

संजय सोंधी उप सचिव
भूमि एवं भवन विभाग
दिल्ली सरकार

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसे एसएंडपी, मूडीज और फिच भारत की आर्थिक ताकत को कम आंकती हैं और भारत सरकार के सॉवरेन डेट पेपर्स को निम्न निवेश की रेटिंग देती हैं, जो वास्तविकता से परे है। ये एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती को नजरअंदाज करती हैं। भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 12वें से 5वें स्थान पर छलांग लगाई है, फिर भी इन एजेंसियों ने भारत के सॉवरेन डेट को सबसे निचले निवेश ग्रेड या Junk रेटिंग दी है।

यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भारत ने कभी भी अपने कर्ज दायित्वों में चूक नहीं की, फिर भी उसे हमेशा निम्न रेटिंग ही मिलती है। भारत का राजकोषीय घाटा भी संतोषजनक स्थिति में है। केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8% है, जबकि सभी राज्य सरकारों का घाटा 3.2% है, जो कई अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ी, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सराहनीय है। हालांकि निजी क्षेत्र पूंजीगत व्यय में पीछे है, लेकिन सरकार ने इस कमी को पूरा किया है और सकल पूंजी निर्माण 31% है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

कुल कर्ज/जीडीपी अनुपात की बात करें तो जापान का 251%, अमेरिका का 123%, और चीन का लगभग 300% है, जबकि भारत का केवल 81% है। इस मोर्चे पर भी भारत की स्थिति मजबूत है। साथ ही, भारत की अर्थव्यवस्था में कर संग्रह में उछाल देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद, अमेरिका जैसे उच्च राजकोषीय घाटे और भारी कर्ज वाली अर्थव्यवस्था को दूसरी सबसे ऊंची निवेश ग्रेड रेटिंग मिलती है।

भारत को इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से अपनी आर्थिक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि भारत को बेहतर निवेश ग्रेड रेटिंग मिलती है, तो यह इक्विटी और डेट दोनों में विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा, जो भारत की विकास यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

Sanjaysondhi37@gmail.com

दिल्ली में बीजेपी सांसद के घर पर भिड़ गए पार्षद, हाथापाई की आई नौबत; कार्यकर्ताओं ने कराया बीचबचाव

दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के आवास पर भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस वार्ता में दो पार्षद आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद हाथापाई की नौबत आ गई जिससे कार्यकर्ताओं में अफरातफरी मच गई। कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव कर दोनों को शांत किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के जाकिर हुसैन मार्ग स्थित घर पर बृहस्पतिवार को दो पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इससे अन्य कार्यकर्ताओं में अफरातफरी मच गई। फिर कार्यकर्ताओं ने बीचबचाव कराकर दोनों को शांत किया।

दरअसल, सांसद रामवीर सिंह बिधड़ी ने केंद्र की भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने पर अपने आवास पर प्रेस वार्ता रखी थी। इसमें पत्रकारों के अलावा भाजपा के विधायक, जिला अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रसे वार्ता के बाद सांसद मीडिया से बात कर रहे थे। आवास के आंगन में कार्यकर्ता बैठे थे।

कुछ देर में ही हाथापाई की नौबत आ गई

यहां पर ही दिल्ली नगर निगम दक्षिणी जोन के चेयरमैन उम्मेद सिंह और डिप्टी चेयरमैन अनिता भी थे। कुछ देर बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ देर में ही हाथापाई की नौबत आ गई। तभी अन्य कार्यकर्ता में भी अफरातफरी मच गई।

कार्यकर्ता दौड़कर आए और बीच बचाव किया। इसके बाद दोनों को शांत करके अलग अलग कर दिया गया। इसके कुछ देर बाद दोनों ही कार्यक्रम से चले गए। कहासुनी और बहसबाजी का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

यहां पर ही दिल्ली नगर निगम दक्षिणी जोन के चेयरमैन उम्मेद सिंह और डिप्टी चेयरमैन अनिता भी थे। कुछ देर बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ देर में ही हाथापाई की नौबत आ गई। तभी अन्य कार्यकर्ता में भी अफरातफरी मच गई।

कार्यकर्ता दौड़कर आए और बीच बचाव किया। इसके बाद दोनों को शांत करके अलग अलग कर दिया गया। इसके कुछ देर बाद दोनों ही कार्यक्रम से चले गए। कहासुनी और बहसबाजी का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

दिल्ली में ताबड़तोड़ चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान, इस इलाके में निगम ने बुलडोजर से हटाए अवैध कब्जे

पूर्वी दिल्ली में जिला प्रशासन और निगम ने यमुनापार में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। सीमापुरी मेन रोड शास्त्री पार्क खजूरी चौक और करावल नगर समेत कई इलाकों में कार्रवाई की गई। कुछ स्थानों पर विरोध हुआ लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाला। निगम ने कबाड़ जब्त किया और अवैध निर्माणों को तोड़ा।

पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन और निगम ने कई स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान कुछ स्थानों पर विरोध हुआ, लेकिन पुलिस बल ने स्थिति को संभाला।

निगम के शाहदरा उत्तरी जोन की टीम ने पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर सीमापुरी मेन रोड से अतिक्रमण हटाया। इस रोड के एक तरफ पुराना फर्नीचर और इलेक्ट्रानिक उपकरण खरीदने वाले कबाड़ियों ने सड़क किनारे कब्जा किया हुआ था। दूसरी तरफ लोहा, प्लास्टिक और कागज के कबाड़ियों ने अतिक्रमण कर रखा था। इस कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी होती थी।

करीब दो किलोमीटर का हिस्सा अतिक्रमण मुक्त कराया

निगम की टीम ने सड़क किनारे रखा पुराना फर्नीचर बुलडोजर से तोड़ दिया और पांच ट्रक कबाड़ जब्त किया। करीब दो किलोमीटर का हिस्सा अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इसी जोन की टीम ने शास्त्री पार्क से खजूरी चौक और वहां से भजनपुरा कार मार्केट तक कार्रवाई कर सड़क पर लग रही रेहड़ियों को जब्त किया।

करावल नगर काली घटा तक अतिक्रमण हटाया

चांद बाग शेरपुर चौक से करावल नगर काली घटा तक अतिक्रमण हटाया गया। सीलमपुर में एसडीएम के नेतृत्व में गुरुद्वारा रोड पर कार्रवाई कर दुकानों के सामने सड़क तक बने चबूतरे तोड़े गए। वहीं, निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन की टीम ने गीता कोलानी के कई ब्लॉकों में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया। यहां के ब्लाक छह में दुकानों के बाहर रखे काउंटर, चूल्हे निगम की टीम ने जब्त कर लिए। रेहड़ियां भी उठाई गईं।

निगम की टीम ने सड़क किनारे रखा पुराना फर्नीचर बुलडोजर से तोड़ दिया और पांच ट्रक कबाड़ जब्त किया। करीब दो किलोमीटर का हिस्सा अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इसी जोन की टीम ने शास्त्री पार्क से खजूरी चौक और वहां से भजनपुरा कार मार्केट तक कार्रवाई कर सड़क पर लग रही रेहड़ियों को जब्त किया।

करावल नगर काली घटा तक अतिक्रमण हटाया

चांद बाग शेरपुर चौक से करावल नगर काली घटा तक अतिक्रमण हटाया गया। सीलमपुर में एसडीएम के नेतृत्व में गुरुद्वारा रोड पर कार्रवाई कर दुकानों के सामने सड़क तक बने चबूतरे तोड़े गए। वहीं, निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन की टीम ने गीता कोलानी के कई ब्लॉकों में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया। यहां के ब्लाक छह में दुकानों के बाहर रखे काउंटर, चूल्हे निगम की टीम ने जब्त कर लिए। रेहड़ियां भी उठाई गईं।

तेज़ रफ़्तार कार ने दो को रौंदा 27 वर्षीय संदीप यादव की मौके पर हुई मौत

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली: दिल्ली स्थित मंडावली थाने के ठीक कुछ दूरी पर तेज़ रफ़्तार कार ने बुलेट सवार को मारी टक्कर जिसमें एक की मौके पर हुई मौत,दूसरे व्यक्ति कि इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है ! घटना देर रात बीते सोमवार 17 तारीख की है , तेज़ रफ़्तार कार DL10 CJ 4078 ने बुलेट सवार व्यक्ति को रौंदा 27 वर्षीय संदीप यादव की मौके पर मौत हो गई ! दुसरा घयाल व्यक्ति सागर की हालत गंभीर बताई जा रही है घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर जा कर बुलेट को बरामद कर कार चालक को हिरासत में ले लिया आगे की जांच पड़ताल चल रही है मंडावली के निवासी हरि राम यादव ने बताया कि रात्रि के समय संदीप यादव आफिस से वापस घर आ रहा था तभी मंगलम रेडलाइट एरिया पर तेज़ रफ़्तार कार ने रौंद दिया घटना की सीसीटीवी फुटेज भी है लेकिन थाने की पुलिस सीसीटीवी की फुटेज को सार्वजनिक नहीं किया है पीड़ित परिवार को धोखे में रखकर पुलिस कार्रवाई करती नज़र आ रही है ! मंडावली में जिस स्थान पर घटना हुई है, वहां पर स्कूल है उसके ठीक सामने लाल बत्ती है घटना की सीसीटीवी फुटेज है लेकिन पुलिस जांच पड़ताल करने में आना कानी करती दिख रही है !

मंडावली थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है

कितना सफल रहा कांग्रेस का युवाओं को रोजगार देने का प्रयास? चौंका देगा आंकड़ा; हाथोंहाथ मिला जॉब लेटर

दिल्ली में कांग्रेस ने युवाओं के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जिसमें 161 कंपनियों ने भाग लिया। 8500 युवाओं ने पंजीकरण कराया और 3391 को मौके पर ही नौकरी मिली। कांग्रेस नेताओं ने इसे राहुल गांधी के विजन और युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश बताया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

नई दिल्ली। दिल्ली में अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस बृहस्पतिवार को युवाओं तक पहुंचने में सफल रही। मौका था भारतीय युवा कांग्रेस (आइवाइसी) एवं प्रदेश कांग्रेस द्वारा तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जाब फेयर के आयोजन का। सुबह 10 से शाम पांच बजे तक चले इस रोजगार मेले में बेरोजगार युवाओं की भीड़ देखते ही बनी। ऐसे में पार्टी के अनेक राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय नेता भी उनसे संवाद करने के लिए वहां पहुंचे।

इस रोजगार मेले में टाटा अलायन्स, फ्लिपकार्ट, जिप्टो, वोल्टास, टेक महिंद्रा, पेटीएम, आदित्य बिरला, हिटाची, अर्बन क्लैप, एचडीएफसी, ब्लिंकिट और अमेजन जैसी 161 कंपनियां पहुंची थीं। मेले में लगभग 8500 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। लगभग 7500 युवाओं के इंटरव्यू हुए जबकि 3391 युवाओं को हाथोंहाथ जॉब लेटर मिले। साथ ही साथ कई युवाओं को कंपनियों के एचआर द्वारा दूसरे राउंड के लिए भी आमंत्रित किया गया है।

राहुल गांधी युवाओं को रोजगार देने की कोशिश में जुटे

इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की ही है। भाजपा ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था पर जमीन पर कुछ भी नहीं है। देश के युवाओं को आज रोजगार चाहिए, और राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो निरंतर इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं।

राहुल गांधी के विजन पर यकीन रखने वालों की मुहिम

आइवाइसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि भाजपा ने हमें बेरोज़गारी दी, हमने उसके जवाब में रोज़गार का मेला खड़ा कर दिया। युवा कांग्रेस का रोजगार मेला सिर्फ़ एक इवेंट नहीं, ये राहुल गांधी के विज़न पर यक़ीन रखने वालों की मुहिम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा "ये रोज़गार मेला कोई साधारण आयोजन नहीं बल्कि युवाओं को नौकरी दिलाने की एक ठोस कोशिश है।

कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

रोजगार मेले में एआइसीसी महासचिव सचिन पायलट, एआइसीसी प्रभारी काजी निजामुद्दीन, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, राजस्थान विधानसभा के नेता विपक्ष टीकाराम जूली, इंटरनेट मीडिया विभाग की चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत, पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक, किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पूनिया, एआइसीसी प्रभारी कन्हैया कुमार तथा पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी पहुंचे।

आइवाइसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि भाजपा ने हमें बेरोज़गारी दी, हमने उसके जवाब में रोज़गार का मेला खड़ा कर दिया। युवा कांग्रेस का रोजगार मेला सिर्फ़ एक इवेंट नहीं, ये राहुल गांधी के विज़न पर यक़ीन रखने वालों की मुहिम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा "ये रोज़गार मेला कोई साधारण आयोजन नहीं बल्कि युवाओं को नौकरी दिलाने की एक ठोस कोशिश है।

दिल्ली के चार अस्पतालों को लेकर एक्शन में एलजी सक्सेना, मुख्यमंत्री-मंत्री समेत तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बुलाई आपात बैठक

दिल्ली गेट के पास स्थित सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एलजी ने एक बैठक की। बैठक में छात्रों और डॉक्टरों के आवास अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर चर्चा हुई। एलजी ने अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जिसमें आवास निर्माण पुलिस की तैनाती और अतिक्रमण हटाना शामिल है। उन्होंने जल्द ही परिसर का दौरा करने का भी निर्णय लिया।

नई दिल्ली। दिल्ली गेट के समीप स्थित चार बड़े सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और वहां मरीजों को और बेहतर सुविधाएं बहाल करने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने बृहस्पतिवार को राजनिवास में एक आपातकालीन बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही चिकित्सा संस्थानों के डीन एवं निदेशकों के अनुरोध पर बुलाई गई इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान बात सामने आया कि पिछले कुछ वर्षों में वहां छात्रों और डाक्टरों की सुरक्षा, आवास की भारी कमी, ढहते नागरिक बुनियादी ढांचे और अतिक्रमण के कारण जगह की भारी कमी को लेकर अत्यंत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है।

डॉक्टरों-मेडिकल छात्रों के लिए आवास की भारी कमी

बैठक में सामने आया कि इन अस्पतालों में डॉक्टरों-मेडिकल छात्रों के लिए आवास की भारी कमी है ही, इन्हें आवंटित भूमि पर भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है। इन चिकित्सा संस्थानों के परिसर में अवैध पार्किंग से लेकर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक स्थल और स्कूल तक चल रहे हैं, जिससे इनमें आसानी से चलना मुश्किल है।

इनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) संरक्षित स्मारक भी हैं, जिसपर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। यही नहीं, इन अस्पताल परिसरों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है और ड्रग्स की तस्करी भी धड़ल्ले से हो रही है, जिससे यहां सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सबसे बड़े मेडिकल कॉम्प्लेक्स की स्थिति पर हैरानी

एलजी ने राजधानी के बीचों-बीच स्थित शहर के इस सबसे बड़े मेडिकल कॉम्प्लेक्स की स्थिति पर हैरानी और निराशा व्यक्त की, जो सत्ता की नाक के नीचे है। वहीं सीएम ने पिछली सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से राजनीतिक संरक्षण की ओर इशारा किया, जिसके कारण वर्तमान में यह स्थिति बनी हुई है।

बैठक में मौजूद डीन और निदेशकों ने एलजी, सीएम और मंत्री को बताया कि छात्र और डाक्टर उनसे मिलकर अपना पक्ष रखने का अनुरोध कर रहे हैं। अगर अनुमति दी जाती है, तो उनका एक प्रतिनिधिमंडल उनके मामले को पेश करेगा।

सुरक्षा एवं सुविधाओं के संबंध में कई निर्देश जारी किए

बैठक के दौरान प्रेजेंटेशन देखने के बाद एलजी और सीएम ने परिसर में कानून और व्यवस्था, नागरिक बुनियादी ढांचे, सुरक्षा एवं सुविधाओं के संबंध में कई निर्देश जारी किए। यह निर्णय लिया गया कि एलजी, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री स्थिति का जायजा लेने के लिए परिसर का दौरा करेंगे। छात्रों और डाक्टरों का प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द सीएम से मुलाकात करेगा।

बैठक के बाद जारी निर्देश

लोक निर्माण विभाग को कम से कम 4000 छात्रों और डॉक्टरों के लिए आवास और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक व्यापक योजना और अनुमान तैयार करने का निर्देश दिया गया।

दिल्ली पुलिस को परिसर में पर्याप्त पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित करने और आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जो छात्रों ने बताया था कि वे उन्हें धमका रहे हैं।

पुलिस को विशेष रूप से परिसर के अंदर शराब तस्करों और ड्रग कार्टेल के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

अस्पताल अधिकारियों के साथ-साथ सभी भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसियों को इन चिकित्सा संस्थानों को आवंटित भूमि का तुरंत सर्वेक्षण करने और उस पर अतिक्रमण की पहचान करने का निर्देश दिया गया। जहां तक धार्मिक संरचनाओं का सवाल है, यह निर्देश दिया गया कि उन्हें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत धार्मिक समिति को भेजा जाए।

एमसीडी और जीएनसीटीडी के शिक्षा विभाग को परिसर में अवैध रूप से संचालित स्कूलों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।

एएसआई को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उसके द्वारा संरक्षित स्मारकों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश।

तस्वीरों के साथ कार्रवाई रिपोर्ट को समय-समय पर एलजी सचिवालय, सीएमओ और स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करने को कहा गया।

धर्म का एक दशक: मोदी युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण

गजेन्द्र सिंह शेखावत

2014 में शुरू से ही यह स्पष्ट था कि मोदी सरकार के तहत संस्कृति अब सजावटी नहीं रहेगी, बल्कि यह मूलभूत होगी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। अब दुनिया भर में लाखों लोगों को एक प्राचीन भारतीय परंपरा का जश्न मनाते देखा जा रहा है, जो शरीर, मन और आत्मा को आपस में जोड़ता है।

जनवरी 2024 में, जब पावन नगरी अयोध्या में सूर्योदय हुआ। सदियों से लुप्त हो चुकी प्रार्थना अब आखिरकार गुंजायमान होने लगी थी। श्री राम की अपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महज एक धार्मिक उपलब्धि नहीं थी। यह सभ्यता के उद्धार का क्षण था। सदियों के आक्रमण, औपनिवेशिक विकृति और राजनीतिक देरी के बाद, मंत्रों से गूंजता हुआ और इतिहास के स्पंदन सहित, बलुआ पत्थर में उकेरा गया यह मंदिर शान से खड़ा था। यह सिर्फ वास्तुकला के बारे में नहीं था, यह एक घायल आत्मा के उपचार के बारे में था। श्री राम की अपनी जन्मभूमि पर वापसी ने उस राष्ट्र की आस्था को फिर से जागृत कर दिया, जिसने लंबे समय तक अपने दिल में निर्वासन की खामोशी को समेटे रखा था।

कुछ महीने पहले, भारत की प्राचीन आस्था का एक और प्रतीक चुपचाप अपने सही स्थान पर लौट आया। नई संसद के उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया। यह एक पवित्र राजदंड है, जिसे 1947 में तमिल अधीनमों ने सत्ता के धार्मिक हस्तांतरण को चिह्नित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया था। दशकों से, इसे भुला दिया गया था, समुचित स्थान से वंचित किया गया, और एक प्रचलित राजदंड के तौर पर खारिज कर दिया गया था। इसकी स्थापना केवल स्मरण का कार्य नहीं था - यह एक शक्तिशाली घोषणा थी कि भारत अब खुद को उधार की आंखों से नहीं देखेगा। सेंगोल ने साम्राज्य के अवशेषों का नहीं, बल्कि धार्मिकता पर आधारित शासन का प्रतिनिधित्व किया। यह भारत की अपनी राज्य कला और आध्यात्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण आलिंगन था, जिसे उपनिवेशवाद के बाद के क्रम में लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था।

इतना ही नहीं, इन क्षणों ने एक गहरे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकेत दिया। यह एक सभ्यतागत गतिविधि के तौर पर ग्यारह परिवर्तनकारी वर्षों में सामने आएगी।

2014 में शुरू से ही यह स्पष्ट था कि मोदी सरकार के तहत संस्कृति अब सजावटी नहीं रहेगी, बल्कि यह मूलभूत होगी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। अब दुनिया भर में लाखों लोगों को एक प्राचीन भारतीय परंपरा का जश्न मनाते देखा जा रहा है, जो शरीर, मन और आत्मा को आपस में जोड़ता है। योग केवल एक स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या भर नहीं है, बल्कि यह पिछले कुछ वर्षों में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक निर्यात भी बन गया है। आयुष मंत्रालय के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के पुनरुद्धार को संस्थागत बल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर पहुंचने में मदद मिली।

समानांतर रूप से, सरकार ने संस्कृत, तमिल, पाली और प्राकृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं को संरक्षित करने, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और उस्ताद एवं हमारी धरोहर जैसी योजनाओं के तहत लुप्तप्राय लोक कलाओं

और शिल्पों का समर्थन करने के लिए मिशन शुरू किए।

भारत की ऐतिहासिकों इमारतों में भी नई जान आ गई। 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण केवल व्यापकता के बारे में नहीं था, बल्कि एक गाथा को पुनः प्रतिष्ठित करने जैसा था। सरदार वल्लभभाई पटेल लंबे समय से ओझल हो रहे थे। उनको राष्ट्रीय स्मृति में सबसे आगे रखा गया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक था। यह औपनिवेशिक प्रतीकवाद से देशी जवाबदेही की ओर बदलाव का भी प्रतीक था।

तमिलनाडु के महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच 2019 की अनौपचारिक शिखर वार्ता की तुलना में शायद कोई भी कूटनीतिक वार्ता इस बदलाव को बेहतर तरीके से नहीं दर्शाती है। दिल्ली के गलियारों से दूर, प्राचीन बंदरगाह का नगर, जो कभी पल्लव राजवंश और भारत-चीनी समुद्री संबंधों का एक संपन्न केंद्र होने के साथ-साथ दो सभ्यताओं के बीच वार्ता की पृष्ठभूमि बन गया। जब नेता चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और पत्थर के रथों के बीच चले, तो भारत ने न केवल भूगोल, बल्कि इतिहास और न केवल प्रोटोकॉल, बल्कि विरासत को भी प्रस्तुत किया। यह अपने सबसे सूक्ष्म और सबसे मजबूत रूप में सॉफ्ट पावर था।

यह सांस्कृतिक लोकाचार अन्य तरीकों से भी भारत की वैश्विक कूटनीति में प्रवाहित हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व के नेताओं को राजकीय उपहार के तौर पर पट्टचित्र पेंटिंग से लेकर बच्चों के लिए लाख के खिलौने भेंट किए गए, जो अपने साथ भारत के कारीगरों और कालातीत परंपराओं के संदेश लेकर गए।

2023 में जी-20 की अध्यक्षता एक और सांस्कृतिक उपलब्धि साबित हुई। दिल्ली के डिप्लोमेटिक हॉल तक सीमित न रहकर, यह शिखर सम्मेलन सांस्कृतिक पहचान का अखिल भारतीय उत्सव बन गया। आदिवासी कला प्रदर्शनों से लेकर शास्त्रीय प्रदर्शनों तक, भारत ने न केवल अपनी नीतिगत गहराई, बल्कि अपनी आत्मा का भी प्रदर्शन किया। हर प्रतिनिधिमंडल भारत के रंगों, व्यंजनों, शिल्प और चेतना में डूबा हुआ था। संदेश स्पष्ट था: भारत भूतकाल की सभ्यता नहीं है - यह जीवंत, सशक्त और आत्मविश्वास से परिपूर्ण वैश्विक सभ्यता है।

इन वर्षों के दौरान, 600 से अधिक चोरी की गई कलाकृतियां विदेशी संग्रहालयों और संग्रहकर्ताओं से वापस लाई गईं, जिनमें मूर्तियां, शिलालेख और पांडुलिपियां शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक की वापसी न केवल कला की बल्कि सम्मान की बहाली थी। इसी तरह, गुरु गोविंद सिंह के वीर शहजादों की शहादत को याद करने के लिए वीर बाल दिवस की स्थापना की गई, जबकि जनजातीय गौरव दिवस ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय केन्द्र में लाया। महामारी भी सांस्कृतिक लौ को मद्धिम नहीं कर पाई। वर्चुअल कॉन्सर्ट, डिजिटल म्यूजियम टूर और "मन की बात" के माध्यम से, प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि कला, कहानियां और सांस्कृतिक गौरव लॉकडाउन के एकांत में भी पुष्पित-पल्लवित होते रहें।

"विकास भी, विरासत भी" के नारे जैसे अभियान में ये सभी समाहित हो गए। यह एक आह्वान है जो आर्थिक विकास को सांस्कृतिक गौरव के साथ-साथ चलने पर जोर देता है। मोदी सरकार के तहत, यह नारा केवल बयानबाजी नहीं था। इसने एक नई दृष्टि को परिभाषित किया। एक दृष्टि, जिसमें जीडीपी वृद्धि, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा आधुनिकीकरण, मंदिर जीर्णोद्धार, आदिवासी गौरव और सभ्यता की गाथा समाहित थे।

भारत आज अपनी पहचान के इर्द-गिर्द नहीं घूमता। बिना किसी पछतावें और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर यह आगे बढ़ता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद प्रगति की बाध्यकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जिसे कभी प्रतिगामी के रूप में खारिज कर दिया गया था। भाजपा के वैचारिक कम्पास में, संस्कृति केवल एक सहायक भर नहीं है, बल्कि धुरी है।

इन ग्यारह सालों में मोदी युग ने केवल सांस्कृतिक नीति को ही ध्यान में नहीं रखा है, बल्कि इसने सांस्कृतिक चेतना को भी जागृत किया है। जो पुनर्स्थापना के तौर पर शुरू हुआ था, वह पुनरुत्थान बन गया। जिन्हें कभी अतीत की स्मृतियों के तौर पर उपेक्षित किया जाता था, वे सभी अब राष्ट्रीय पहचान के केंद्र बन गए हैं। राम मंदिर और सेंगोल हमेशा सांकेतिक प्रतीक बने रहेंगे, लेकिन विरासत की गहराई सामूहिक अहसास में निहित है। भारत का भविष्य तब सबसे उज्ज्वल होगा, जब वह याद रखेगा कि वह कहां से आया है। हम सिर्फ एक लंबा इतिहास वाला देश नहीं हैं, बल्कि हम एक लंबी स्मृति वाली जीवित सभ्यता हैं। और उस स्मृति में, धर्म की निगरानी में, भारत ने फिर से अपनी आवाज पाई है।

- गजेन्द्र सिंह शेखावत,
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, भारत सरकार

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में शामिल हुए विराट जायसवाल, रखा श्रमिकों का पक्ष

सुनील बाजपेई

कानपुर। मलिकानों के पक्ष में श्रम कानून के खुलेआम उल्लंघन के के फल स्वरुप पूरे भारत में श्रमिकों की दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके खिलाफ अनेक बड़े श्रमिक संगठन भी मुखर हो चले हैं। इसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) के 113 वें श्रम सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले भारत के त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने वाले एन एफ आई टी यू महासचिव एल एन सी टी यूनिवर्सिटी भोपाल के उप कुलसचिव डॉ.विराट जायसवाल ने भारतीय श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में असंगठित क्षेत्र, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को मजबूती से प्रस्तुत किया।

बीते कई दशकों से मजदूर श्रमिक कर्मचारी के के हित को लेकर अनेक सफल आंदोलन के अगुआकर हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश महामंत्री राकेश मणि पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉ विराट जायसवाल ने बायोलॉजिकल हजार्डइन द वर्किंग एनवायरमेंटऔर ए आई फ्यूचर का वर्क सत्रों में सत्रों में भाग लेते हुए भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-श्रम पोर्टल, आयुष्मान भारत, सोशल सिक्योरिटी कोड, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना, श्रम सुविधा पोर्टल, तथा महिला शक्ति केंद्र योजना जैसी तमाम योजनाओ को वैश्विक मंच पर साझा किया।

वरिष्ठ श्रमिक नेता राकेश मणि पांडेय ने इसका विवरण देते हुए बताया कि सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व बहुत प्रभावी तरीके से सफलता पूर्वक करने वाले डॉ. जायसवाल ने सीरिया, तुर्की, मिस्र, कुवैत, मॉरिशस, मालदीव के साथ-साथ इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक संवाद कर सांस्कृतिक एवं श्रम आधारित अनुभवों का आदान-प्रदान भी किया, जिससे भारत के नवाचारों और श्रम सुधारों की वैश्विक स्तर पर सराहना भी की गई।

हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव चर्चित श्रमिक नेता राकेश मणि पांडेय ने बताया कि बी आर आई सी एस ट्रेड यूनियन की बैठक जो भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री बी.सुरेन्द्रन के नेतृत्व में जिनेवा में आयोजित हुई, उसमें एन एफ आई टी यू के महासचिव डॉ. विराट जायसवाल ने जानकारी दी कि वर्ष 2026 में भारत बी आर आई सी एस ट्रेड यूनियन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इस दौरान एलएनसीटी ग्रुप के सचिव डॉ. अनुपम चौकसे ने इंडियन काउंसिल ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज आईसीएसआई का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के लघु उद्योगों में हो रहे नवाचार, रोजगार सृजन और श्रमिक कल्याण से जुड़ी पहलों को वैश्विक मंच पर साझा किया।

डॉ जायसवाल ने बताया की केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आई एल ओ सम्मेलन के प्लेनरी सत्र में कहा कि भारत ने रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व प्रगति की है।

उन्होंने यह भी बताया कि 2017 की 6% बेरोजगारी दर घटकर 2024 में केवल 3.2% रह गई है, और 7.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित हुए हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ई-श्रम पोर्टल की मदद से सामाजिक सुरक्षा कवरेज अब 64% से ऊपर पहुंच चुकी है, जिससे 94 करोड़ से अधिक नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।

श्रमिक नेता राकेश मणि पांडे के मुताबिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती वंदना गुरुनानी और संयुक्त सचिव अजोय शर्मा की भी अहम भूमिका रही। साथ ही उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर की भी महत्वपूर्ण मौजूदगी रही।

समस्याओं के खिलाफ श्रमिकों के हित में आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भारत के स्थायी मिशन के प्रमुख एच ई अरिंदम बागची के उत्कृष्ट आतिथ्य और समन्वय के लिए डॉ. जायसवाल ने विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि एन एफ आई टी यू अब आई एल ओ की ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस का आधिकारिक सदस्य बन चुका है, जो महानिदेशक गिल्बर्ट होंगबो की प्रमुख पहल है ,जिसे एन एफ आई टी यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दीपक जायसवाल समेत सभी पदाधिकारी संगठन के लिए गर्व का पल मानते हैं। वहीं डॉ. जायसवाल के स्वदेश लौटने पर एन एफ आई टी यू दिल्ली प्रदेश समिति ने उनका जोरदार भव्य स्वागत भी किया।

पीएम की दो टूक

अब भारत और उसके प्रधानमंत्री मोदी को यह मुद्दा दफन ही कर देना चाहिए। विपक्ष को भी समझना चाहिए कि यह राष्ट्रहित का मुद्दा नहीं है। विपक्ष को इस संदर्भ में मजाकिया टिप्पणियां करने से भी बाज आना चाहिए। सत्ता में आने का उसे भी मौका मिलेगा, तब भी अमरीकी राष्ट्रपति का यही रवैया रहा, तो क्या करेंगे? हमें यह इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि फोन पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की 35 मिनट लंबी बातचीत होने के बावजूद अमरीकी राष्ट्रपति वही पुराना, घिसा-पिटा राग अलाप रहे हैं। बेशक ट्रंप दुनिया की सबसे ताकतवर और संपन्न महाशक्ति के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, तो नरेंद्र मोदी भी सबसे अधिक आबादी, सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था और दुनिया के सबसे व्यापक बाजार भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। भारत की अपनी संप्रभुता, सुरक्षा, सोच और क्षेत्रीय अखंडता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दो टूक समझा दिया कि भारत न तो मध्यस्थता स्वीकार करता है, न भारत-पाक संघर्ष को रोकने में किसी की मध्यस्थता स्वीकार की है और न ही कभी मध्यस्थता स्वीकार करेगा, तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप को कौनसी भाषा समझ में आती है? दरअसल हम भारतीय महानतम चाणक्य की संतति हैं, भाषा के मर्म और संस्कारों को अच्छी तरह समझते हैं। हम किसी राष्ट्राध्यक्ष अथवा प्रधानमंत्री से इस भाषा में नहीं बोल सकते कि ट्रंप 'झूठा' है, गलत बोल रहा है। हमारी कूटनीति की संस्कारी भाषा यही है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभिव्यक्त की है। दिलचस्प यह है कि फोनिक संवाद के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने, कनाडा से वापसी करते हुए, अमरीका आने का आमंत्रण दिया, जिस पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने असमर्थता जता दी।

राष्ट्रपति ट्रंप से एक मुलाकात और बातचीत के लिए राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री कतार लगाए प्रतीक्षारत हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री इस न्योते को अस्वीकार करने का साहस दिखा सके, यही भारत की ताकत और हैसियत है। प्रधानमंत्री मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' और पाकपरस्त आतंकवाद पर राष्ट्रपति ट्रंप को खुलासा करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि गिड़गिड़ाते पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत और संघर्षविराम की गुहार लगाई थी, जिस पर भारत के ही डीजीएमओ ने सैन्य कार्रवाई स्थगित करने की सहमति जताई थी। गौरतलब तो यह है कि पहलगाम नरसंहार की तारीख 22 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पहली बार फोनिक बातचीत अब हुई है, तो मध्यस्थता के लिए किससे आग्रह किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद भारत के लिए 'प्रॉक्सी वॉर' नहीं, बल्कि युद्ध है और हम भविष्य में आतंकवाद से इसी आधार पर निपटेंगे। हमारा मानना है कि ट्रंप को यह समझ आ गया होगा! यदि फिर भी वह पुराना राग अलापते रहना चाहते हैं और पाकिस्तान को अमरीका का 'भरोसेमंद साझेदार' मानना चाहते हैं, तो यह उनकी इच्छा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 'व्हाइट हाउस' में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनरो को लंच का आतिथ्य पेश किया है, तो यह अमरीका की कूटनीतिक, व्यापारिक और सामरिक विवशता हो सकती है। यदि अमरीका को ईरान पर हमला करना है, तो उसे पाकिस्तान के एयरबेस और हवाई क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। ईरान के साथ पाकिस्तान की 900 किमी लंबी सीमा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नूरखान एयरबेस, जिसे भारत के हवाई हमलों ने तबाह कर दिया था, अमरीकी नियंत्रण में है। वहां पाकिस्तान के जनरल भी फटक नहीं सकते। बहरहाल उसकी मरम्मत कराई जा रही है। इसके अलावा, अमरीका की नजर पाकिस्तान के खनिज संसाधनों पर है। अमरीका ने क्रिप्टो करेंसी का मुख्यालय पाकिस्तान को बनाना तय किया है। वहां राष्ट्रपति ट्रंप के सुपुत्र और दामाद यह धंधा संभालेंगे। बहरहाल देश को प्रधानमंत्री, विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयानों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे ही भारत सरकार हैं। अब सब कुछ कहने-सुनने को संसद सत्र का इंतजार करना चाहिए।

विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2025 - मान्यता के माध्यम से एकजुटता

वैश्विक बदलते परिपेक्ष में ज़बरन स्वार्थी पलायन शरणार्थी बनाम भय उत्पीड़न हिंसा व पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन पीड़ति शरणार्थी दुनियाँ की बदलती परिस्थितियों से क्या अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी सम्मेलन 1951व इसके प्रोटोकॉल 1967 के संशोधन की ज़रूरत नहीं?भारत के ऑपरेशन पुशबैक व अमेरिका के टारगेट @3000 इसके सटीक उदाहरण -
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर हर वर्षविश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है जिसकी प्रतिवर्ष एक थीम होती है,जो 20 जून 2025 की थीम मान्यता के माध्यम से एकजुटता है।असल में,दुनिया भर मेंएक बड़ी संख्या में शरणार्थी रहते हैं।इनके साथ आए दिन प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा जैसी कई चुनौतियों के कारण इनको अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है।जिसके बाद इन सभी को कई देशों में पनाह मिल जाती है। वहीं, कई देशों से इनको निकाल भी दिया जाता है। बेशक इन्हें पनाह मिल जाए, लेकिन वो सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाते।शरणार्थी के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इसके साथ ही इस दिन को मनाये जाने का एक अन्य उद्देश्य शरणार्थियों की बुरी दुर्दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उनकी समस्याओं का हल करना है,संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन और इसके प्रोटोकाल 1967, हालांकि भारत अमेरिका ने इसपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं,परंतु इसके अनुसार शरणार्थी सम्मेलन और इसका 1967 प्रोटोकॉल अत्यंत महत्वपूर्ण है शरणार्थी दुनियाँ के सबसे कमजोर लोगों में से हैं। यह सम्मेलन और प्रोटोकॉल उनकी सुरक्षा में मदद करता है। वेएकमात्र वैश्विक कानूनी साधन हैं जो स्पष्ट रूप से एक शरणार्थी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हैं। उनके प्रावधानों के अनुसार, शरणार्थी, कम से कम, किसी दिए गए देश में अन्य विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार के समान मानकों के पात्र हैं और, कई मामलों में,नागरिकों के समान व्यवहार।1951 के कन्वेंशन में कई अधिकार शामिल हैं और यह अपने मेजबान देश के प्रति शरणार्थियों के दायित्वों पर भी प्रकाश डालता है। 1951 के कन्वेंशन की आधारशिला गैर-रिफाउलमेंट का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार, एक शरणार्थी को उस देश में नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। शरणार्थियों द्वारा इस सुरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता है,जिन्हें देश की सुरक्षा के लिए उचित रूप से खतरा माना जाता है, या विशेष रूप से गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उन्हें समुदाय के लिए खतरा माना जाता है। परंतु मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भाववाणी गोंदिया महाराष्ट्र, यह मानता हूं कि अभी 1951 सम्मेलन तथा 1967 के प्रोटोकॉल को संशोधन करने की जरूरत आन पड़ी है?क्योंकि वर्तमान समय में हम अमेरिका- भारत-पाकिस्तान सहित अनेकों देशों में हो रहे गंभीर दंगों व आवर्ज़न विवादों के कारण माहौल दंगों में बदलने की संभावना हो गई है?भारत का ऑपरेशन पुशबैक व अमेरिका का टारगेट@3000 से दंगा भड़क उठा है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे वैश्विक परिपेक्ष में जबरन स्वार्थी पलायन शरणार्थी बनाम भय उत्पीड़न हिंसा व पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन शरणार्थी।

साथियों बात अगर हम अमेरिका की करें तो,वहां भी घुसपैठ का हाल कमोबेश ऐसा ही है। यह जब एक बार घुसपैठिया अंदर आ जाता है तो उसको डिपोर्ट करना भी इसी तरह एक लंबा और विवादास्पद मामला बन जाता है। अमेरिका में लॉस एंजिल्स न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ ऐसे शहर

हैं,जहाँ अधिकारियों को इन घुसपैठियों से पूछताछ करने या उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति नहीं है। ये शहर डिपोर्ट करने के आदेशों या पुलिस के साथ सहयोग करने से साफ इनकार करते हैं, उन्हें कानून प्रवर्तन के राजनीतिक हथियार के रूप में देखते हैं।जून 2025 की शुरुआत से लॉस एंजिल्स में इसी से जुड़ा एक नाटक चल रहा है। यहाँ घुसपैठियों पर जब एक्शन चालू हुआ तो इसके विरोध में प्रदर्शन होने लगे। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और रबर की गोलियाँ चलाई। यहाँ इसके बाद यूनियन नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, सरकार ने इसके बाद टाइटल 10 कानून के तहत 4,000 नेशनल गार्ड सैनिकों और 700 मरीन को तैनात करके जवाब दिया। इसके बाद तो बवाल और बढ़ा। कई कारों को जला दिया गया, सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया, कई पत्रकारों को घायल कर दिया गया। इस पूरे बवाल से ट्रंप सरकार की घुसपैठियों को लेकर नीति और किसी शहर को उनके लिए स्वर्ग बनाने की राजनीति माना जा सकता है। इन सब चक्करों में डिपोर्टेशन और भी कठिन हो जाता है। भले ही अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति सख्त सीमा प्रवर्तन और भूमि से अवैध अप्रवासियों को हटाने के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रणाली और कुछ विशिष्ट शहर इससे कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं।

साथियों बात अगर हम भारत की करें तो यहाँ भी वर्तमान में ऑपरेशन पुशबैक चल रहा है। इसके तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का प्रयास हो रहा है। यह कार्रवाई अभी कुछ हजार लोगों तक ही सीमित है।भारतीय फैशन,असल में एक बार जब अवैध प्रवासी किसी देश में प्रवेश कर जाते हैं तो चाहे वह भारत हो, अमेरिका फिर या यूरोप के देश, तो उन्हें वापस भेजना कानूनी अड़चन, राजनीतिक विरोध और एक्टिविज्म का एक चक्रव्यूह बन जाता है। कायदा तो यह होना चाहिए कि किसी देश में अवैध रूप से रहने वालों को उठा कर सीधे वापस भेज दिया जाना चाहिए। हालाँकि, यह लंबी अदालती लड़ाइयों, एक्टिविज्म और कानूनी दाँवपेंच में बदल गया है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ भारत जैसे देशों में घुसपैठियों को बाहर निकालना मुश्किल का काम है, वहीं पाकिस्तान धड़ाधड़ अफगानिस्तान के लोगों को निर्वासित कर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि फरवरी 2025 तक, पाकिस्तान ने 8 लाख़ से ज़्यादा अफ़गानों को बिना किसी बवाल के डिपोर्ट कर दिया है।

साथियों बात अगर हम भारत अमेरिका के 1951 के शरणार्थी सम्मेलन व1967 के प्रोटोकॉल में शामिल नहीं होने की करें तो, भारत शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि भारत कानूनी रूप से इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा बाध्य नहीं है, जो शरणार्थियों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं और देशों को उन्हें वापस अपने देशों में भेजने से रोकते हैं। हालांकि, भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों को मानवीय आधार पर स्वीकार किया है और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया है। भारत का मानना है कि शरणार्थी समस्या एक द्विपक्षीय मुद्दा है और स्थिति सामान्य होने पर शरणार्थियों को अपने देशों में वापस लौट जाना चाहिए। भारत में शरणार्थियों के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, सभी व्यक्तियों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वे भारत के नागरिक हों या नहीं। इसका मतलब है कि शरणार्थियों को भी इस अधिकार से सुरक्षा मिलती है, और उन्हें मनमाने ढंग से वापस नहीं भेजा जा सकता है। भारत में शरणार्थी समस्या के समाधान के लिए एक स्पष्ट शरणार्थी नीति की आवश्यकता है जो शरणार्थियों के प्रबंधन के लिएपारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था का निर्माण करे। अमेरिका 1951 के अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी सम्मेलन में शामिल नहीं है, लेकिन उसने 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, 1967 का प्रोटोकॉल 1951 के सम्मेलन के दायरे को व्यापक बनाता है,इसका मतलब है कि अमेरिका ने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कुछ दायित्वों को स्वीकार किया है, लेकिन सभी दायित्वों को नहीं, 1951 का शरणार्थी सम्मेलन शरणार्थियों की परिभाषा और उन्हें प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को निर्धारित करता है, 1980 का शरणार्थी अधिनियम अमेरिकी आव्रजन कानून में शरणार्थी की परिभाषा और शरण की प्रक्रिया को शामिल करता है. इस अधिनियम में, अमेरिका ने 1967 के प्रोटोकॉल के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की बात कही है।

साथियों बात अगर हम सही अर्थो में शरणार्थी दिवस के समर्पित पीड़ितों की करें तो, बता दें कि विश्व शरणार्थी दिवस उन लोगों के लिए समर्पित दिन है, जो किसी मजबूरी के कारण अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर होते हैं और वहां पर कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं. दुनियाभर के कई देशों में देखा गया है कि लोग आपदा, बाढ़, किसी महामारी, युद्ध के कारण, हिंसा समेत अन्य कारणों से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर में ऐसे लोगों के मदद और उनके संघर्षों के लिए इस दिन को उनके लिए समर्पित किया है. इतना ही नहीं इन शरणार्थी को प्रेरित किया जाता है, वह दूसरे देशों में जाकर खुद के जीवन को दोबारा से शुरू कर सकते हैं. जिससे उन्हें और उनके परिवार को वहां पर नया जीवन मिले और उन्हें जीवन जीने के लिए बेहतर सुविधाएं भी मिल सके।

अतः अगर हम अपरूप पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2025 - मान्यता के माध्यम से एकजुटता वैश्विक बदलते परिपेक्ष में ज़बरन स्वार्थी पलायनशरणार्थी बनाम भय उत्पीड़न हिंसा व पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन पीड़ति शरणार्थी।दुनियाँ की बदलती परिस्थितियों से क्या अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी सम्मेलन 1951व इसके प्रोटोकॉल 1967 के संशोधन की ज़रूरत नहीं?भारत के ऑपरेशन पुशबैक व अमेरिका के टारगेट@3000 इसके सटीक उदाहरण हैं।

जून 2025 में जीप कारें पर बंपर डिस्काउंट, 3.9 लाख तक की मिल रही छूट

परिवहन विशेष न्यूज

जीप इंडिया जून 2025 में Compass Meridian और Grand Cherokee पर भारी छूट दे रही है। इन SUV पर 3.9 लाख रुपये तक का डिस्काउंट कैश डिस्काउंट फ्री एक्सेसरीज और एक्सचेंज ऑफर शामिल हैं। Compass में 2.0-लीटर इंजन है जबकि Meridian में 5 और 7-सीटर विकल्प उपलब्ध हैं। Grand Cherokee में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है और इस पर जीप वेव एक्सक्लूसिव ओनरशिप प्रोग्राम की मेंबरशिप भी मुफ्त मिल रही है।

नई दिल्ली। जीप इंडिया ने जून 2025 में अपनी पॉपुलर SUV Jeep Compass, Meridian और Grand Cherokee पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ ही जीप की इन गाड़ियों पर और भी कई ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, फ्री एक्सेसरीज, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर जैसे बेनेफिट्स शामिल है। आइए जानते है कि Jeep Compass, Meridian और Grand Cherokee पर जून 2025 में कितना डिस्काउंट मिल रहा है।

Jeep Compass पर डिस्काउंट

जून 2025 में Jeep Compass पर कुल 2.95 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें कैश डिस्काउंट, फ्री एक्सेसरीज, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर शामिल है। इसे पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ पेश की जाती थी, लेकिन अब यह केवल 170hp की पावर जनरेट करने वाली 2.0-लीटर इंजन के साथ पेश की जाती है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स आता है। भारत में Jeep Compass की एक्स-शोरूम कीमत 18.99 लाख से 32.41 लाख रुपये के बीच है।

Jeep Meridian पर डिस्काउंट

जीप मेरिडियन पर 3.9 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। यह SUV अब 5-सीटर बेस वेरिएंट और तीन 7-सीटर वेरिएंट भारत में मिलती है। इसके MY2024 मॉडल्स पर 1.3 लाख रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेरिडियन और कंपास का इंजन एक जैसा ही है। Jeep Meridian की एक्स-शोरूम कीमत 24.99 लाख से 38.79 लाख रुपये के बीच है।

Jeep Grand Cherokee पर डिस्काउंट

जून 2025 में जीप ग्रैंड चेरोकी पर 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे खरीदने पर लोगों को जीप वेव एक्सक्लूसिव ओनरशिप प्रोग्राम की मुफ्त मेंबरशिप भी दिया जा रहा है, जिसमें वारंटी, एडवेंचर सर्विस समेत कई सुविधाएं शामिल है। इसमें 272hp की पावर जनरेट करने वाला 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। Jeep Grand Cherokee की एक्स-शोरूम कीमत 67.50 लाख रुपये से लेकर 69.04 लाख रुपये के बीच है।

मर्सिडीज ने इन गाड़ियों के लिए जारी किया रिकॉल, गाड़ी में आग लगने का है खतरा

परिवहन विशेष न्यूज

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने S Class GLC SL 55 और EQS जैसे मॉडलों को रिकॉल किया है। यह फैसला आग लगने के खतरे को देखते हुए लिया गया है। कंपनी इन गाड़ियों में तकनीकी खराबी को मुफ्त में ठीक करेगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करें और अपनी कार का वीआईएन चेक करवाएं।

नई दिल्ली। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज इंडिया अपने कुछ पॉपुलर मॉडल्स के लिए रिकॉल जारी किया है, इस लिस्ट में S Class, GLC, SL 55 और EQS शामिल है। कंपनी ऐसा फैसला कंपनी ने फायर रिस्क को देखते हुए लिया है, ताकि कार मालिकों की सेफ्टी को बेहतर किया जा सकें। आइए विस्तार में जानते हैं कि Mercedes ने इन गाड़ियों को रिकॉल की वजह से किया है और आपको क्या करना चाहिए।

रिकॉल का कारण

Mercedes-Benz ने S Class, GLC, SL 55 और EQS सेडान में एक तकनीकी खराबी को पाया है, जिसकी वजह से गाड़ियों में आग लगने का खतरा हो सकता है। यह समस्या इंजन या इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है। रिकॉल का मकसद इन खामियों को ठीक करना है।

Mercedes की ये गाड़ियां हुई प्रभावित

मर्सिडीज-बेंज की रिकॉल हुई इन गाड़ियों में S Class, GLC, SL 55 और EQS सेडान है। S Class को वीआईपी और शानदार ड्राइविंग के लिए जाना जाता है। GLC एक कॉम्पैक्ट SUV है। AMG SL 55 एक स्पोर्टी और परफॉर्मेंस कार है। EQS सेडान एक इलेक्ट्रिक कार है, जो कई प्रीमियम फीचर्स से लैस है।

आपको क्या करना होगा?

कंपनी की तरफ से ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वह अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करें और अपनी कार का VIN (व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर) चेक करवाएं, ताकि यह पता चल सके कि उनकी कार रिकॉल लिस्ट में है या नहीं। इसके बाद कंपनी अपने अधिकृत सर्विस सेंटर्स के जरिए प्रभावित कारों की जांच करेगी। कंपनी मुफ्त में खराबी को ठीक करेगी, जिसमें पार्ट्स बदलने या सॉफ्टवेयर अपडेट शामिल हो सकता है। कंपनी की तरफ से इस समस्या का निपटारा मुफ्त में किया जाएगा। आपको अपने डीलर से अपॉइंटमेंट लेकर गाड़ी को चेक करवाना होगा। अगर आप अपनी कार में किसी असामान्य गंध या धुएं का पता चलें, तो तुरंत उसे बंद करें और सर्विस सेंटर से मदद लें। वहीं, अगर आपकी कार रिकॉल लिस्ट में है, तो बारिश में ऐसी का इस्तेमाल सही से करें और डीफ्रॉस्ट मोड का इस्तेमाल करें।

कंपनी की तरफ से ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वह अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करें और अपनी कार का VIN (व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर) चेक करवाएं, ताकि यह पता चल सके कि उनकी कार रिकॉल लिस्ट में है या नहीं। इसके बाद कंपनी अपने अधिकृत सर्विस सेंटर्स के जरिए प्रभावित कारों की जांच करेगी। कंपनी मुफ्त में खराबी को ठीक करेगी, जिसमें पार्ट्स बदलने या सॉफ्टवेयर अपडेट शामिल हो सकता है। कंपनी की तरफ से इस समस्या का निपटारा मुफ्त में किया जाएगा। आपको अपने डीलर से अपॉइंटमेंट लेकर गाड़ी को चेक करवाना होगा। अगर आप अपनी कार में किसी असामान्य गंध या धुएं का पता चलें, तो तुरंत उसे बंद करें और सर्विस सेंटर से मदद लें। वहीं, अगर आपकी कार रिकॉल लिस्ट में है, तो बारिश में ऐसी का इस्तेमाल सही से करें और डीफ्रॉस्ट मोड का इस्तेमाल करें।

आ गई उड़ने वाली फ्लाइंग बाइक; ट्रैफिक जाम के झंझट से मिलेगा छुटकारा, उड़कर पहुंच जाएंगे घर से ऑफिस

परिवहन विशेष न्यूज

चीन की कंपनी Kuickwheel ने Skyrider X6 नाम से उड़ने वाली मोटरसाइकिल पेश की है। यह जमीन पर चलने के साथ हवा में भी उड़ सकती है जिसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपये है। इसमें 10.5 kWh का बैटरी पैक है जो जमीन पर 200 किमी और हवा में 20 मिनट तक की दूरी तय कर सकती है। इसमें ऑटोमेटेड टेकऑफ और लैंडिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी हैं।

नई दिल्ली। ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक नया रोमांच शुरू हो गया है। चीन की कंपनी Kuickwheel ने उड़ने वाली मोटरसाइकिल को पेश किया है, जिसका नाम Skyrider X6 है। यह मोटरसाइकिल जमीन पर चलने के साथ-साथ हवा में भी उड़ सकती है। इसे 69,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 57 लाख रुपये) की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से आप अपने घर से सीधा उड़कर ऑफर पहुंच सकते हैं। आइए विस्तार में Kuickwheel Skyrider X6 के बारे में जानते हैं।

Skyrider X6 का डिजाइन

इसे डुअल-मोड कॉन्फिगरेशन के साथ बनाया गया है, जिसकी मदद से यह जमीन और हवा दोनों जगह पर कार कर सकती है। जमीन पर यह एक रिवर्स ट्राइक की चलती है, जिसमें मिड-माउंटेड रियर-व्हील ड्राइव सिस्टम लगा है। हवा उड़ने के लिए इसमें 6 एक्सीस और 6-रोटर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को लगाया गया है।

Skyrider X6 का बैटरी और रेंज

इसमें 10.5 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जिसे डीसी फास्ट चार्जिंग से एक घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। यह जमीन पर 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और एक बार चार्ज में 200 किमी तक की दूरी तय कर सकती है। वही हवा में उड़ान के दौरान इसकी स्पीड 72 किमी प्रति घंटे है और यह करीब 20 मिनट तक हवा में रह सकती है। इसको लेकर कंपनी का कहना है कि इससे छोटी दूरी का सफर और आपात स्थिति में बहुत उपयोगी हो सकती है, जैसे ट्रैफिक से बचना या जल्दी कहीं पहुंचना।

Flying Bike के सेफ्टी फीचर्स

इसमें कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। Skyrider X6 में ऑटोमेटेड टेकऑफ और लैंडिंग, रूट प्लानिंग, जॉयस्टिक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही रिजर्व प्रोपल्शन और कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। इसमें अगर एक मोटर फेल हो जाए, तो दूसरा काम करता है। इसमें बैलिस्टिक पैराशूट भी दिया गया है, जो इसमें किसी तरह के खराबी आने पर अपने आप खुल जाता है।

स्पोर्टी अवतार में आएगी नई होंडा सिटी, शानदार और प्रीमियम फीचर्स से होगी लैस

परिवहन विशेष न्यूज

होंडा कार्स भारतीय बाजार में Honda City का नया स्पेशल एडिशन लाने की तैयारी में है। कंपनी ने टीजर जारी कर स्पोर्टी लाइफ के लिए तैयार रहने को कहा है। उम्मीद है कि यह होंडा सिटी स्पोर्ट्स एडिशन होगा जिसमें कॉस्मेटिक बदलाव और स्पोर्टी रेड कलर एलिमेंट्स मिलेंगे। इसमें 1.5L का पेट्रोल इंजन होगा। इसका मुकाबला स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना से होगा।

नई दिल्ली। होंडा कार्स भारतीय बाजार में अपनी गाड़ियों की बिक्री के लिए नए-नए एडिशन लेकर आ रही है। हाल ही में कंपनी ने एलिवेट का नया ट्रिम लेकर आई है। कंपनी होंडा सिटी का भी नया स्पेशल एडिशन लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने एक टीजर भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी सीट बेल्ट कस लें और स्पोर्टी लाइफ के लिए तैयार हो जाएं। बने रहें! इसके अलावा कंपनी ने और किसी तरह की जानकारी को शेयर नहीं किया है। हमे उम्मीद है कि यह Honda City Sporty Edition हो सकता है। आइए जानते हैं कि अगर होंडा सिटी स्पोर्ट्स एडिशन आता है, तो उसमें कौन-कौन से फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं?

कितनी होगी कीमत?

होंडा भारत में सिटी सेडान का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इसके बेस SV पेट्रोल MT वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.38 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट ZX पेट्रोल CVT की एक्स-शोरूम कीमत 16.65 लाख रुपये है। कंपनी होंडा सिटी का एपेक्स एडिशन फरवरी 2025 में लॉन्च कर चुकी है, अब कंपनी होंडा सिटी की सेल को बढ़ाने के लिए Honda City Sporty Edition लाने जा रही है।

कैसा होगा लुक?

सिटी स्पोर्ट्स एडिशन को टॉप-स्पेक ZX ट्रिम लेवल पर रखा जा सकता है। इस स्पेशल एडिशन में केवल कॉस्मेटिक अपग्रेड देखने के लिए मिल सकता है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देंगे। इसके बाहर की तरफ कुछ स्पोर्टी एलिमेंट्स को शामिल किया जा सकता है, जो इसके स्पोर्टी लुक को बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें आगे और पीछे के बंपर पर ब्लैक ट्रिम्स, ब्लैक ORVMs (आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स), ब्लैक लिप स्पॉइलर दिया जा सकता है। इसके बाहर की तरफ ब्लैक व्हील्स या फिर एक बिल्कुल नए व्हील्स दिए जा सकते हैं।

स्पोर्ट्स एडिशन का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें, तो डैशबोर्ड, सीट अपहोल्स्ट्री, सेंटर कंसोल और अन्य एलिमेंट्स पर स्पोर्टी रेड कलर एलिमेंट्स मिलने की उम्मीद है। इसके स्टीयरिंग व्हील, गियर सेलेक्टर और सीट अपहोल्स्ट्री पर लाल सिलाई भी देखी जा सकती है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देने का काम करेंगे।

कितना दमदार होगा इंजन?

नए Honda City Sporty Edition में 1.5L नेचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 120 PS की पीक पावर और 145 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। इसके इंजन को 5-स्पीड मैनुअल या CVT से जोड़ा जा सकता है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Volkswagen Virtus, Skoda Slavia और Hyundai Verna जैसी C+ सेगमेंट सेडान से देखने के लिए मिलता है।

रीज़ मोटो ने लॉन्च किया हेल्डेन हेलमेट, बेहतरीन डिजाइन और दमदार सेफ्टी मिलेगी, कीमत 3499 रुपये

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में टू व्हीलर चलाने वालों के लिए कई तरह के उत्पाद ऑफर करने वाली निर्माता Reise Moto Helden Helmet Launch राइज मोटो की ओर से नए Helden हेलमेट को लॉन्च कर दिया गया है। इस हेलमेट में किस तरह की सुरक्षा को दिया गया है। किस तरह के फीचर्स के साथ इसे ऑफर किया गया है। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में हर महीने लाखों की संख्या में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। इसी के साथ बड़ी संख्या में हेलमेट की भी जरुरत होती है। भारत में हेलमेट निर्माता Reise Moto की ओर से नए हेलमेट को लॉन्च (Reise Moto Helden Helmet Launch) किया गया है। इस हेलमेट में किस तरह के फीचर्स को दिया गया है, यह कितना सुरक्षित होगा। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च हुआ Reise Moto Helden हेलमेट

राइज मोटो की ओर से भारतीय बाजार में नए हेलमेट के तौर पर Reise Moto Helden को लॉन्च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस हेलमेट को सुरक्षित बनाने के साथ ही फीचर्स पसंद करने वालों के लिए ऑफर किया गया है।

कैसे हैं फीचर्स

राइज मोटो की ओर से हेल्डेन हेलमेट में 108 डिग्री वाइड एंगल वाला एंटी स्क्रैच वाइजर को दिया गया है। जिससे सड़क पर राइड के दौरान ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी मिलती है। इसके साथ ही इंटीग्रेटिड ब्लूटूथ पॉकेट को भी इसमें दिया गया है जिसके जरिए आसानी से स्मार्टफोन को कनेक्ट किया जा सकता है। हेलमेट में बेहतर एयर फ्लो के लिए फ्रंट और रियर में वेंट्स को भी दिया गया है।

कितना है सुरक्षित

जानकारी के मुताबिक इस हेलमेट को एडवांस पॉलीकार्बोनेट कंपोजिट शेल के साथ बनाया गया है। जिससे यह वजन में हल्का और काफी मजबूत हेलमेट में से एक बन जाता है। निर्माता की ओर से इस हेलमेट को ISI, DoT और ECE 22.05 जैसी बेहतरीन सुरक्षा के साथ ऑफर किया जा रहा है।

अधिकारियों ने कही यह बात

राइज मोटो के फाउंडर और एमडी योगेश महांसारिया ने कहा कि राइज में, हमारा मानना है कि सुरक्षा एक जरूरत है, विलासिता नहीं। हमारी नई हेलमेट रेंज में बेहतरीन एयरोडायनामिक डिज़ाइन है, जिससे लोग इसे रोजाना यात्रा करते हुए पहने या फिर वीकेंड पर रोमांच के लिए बाहर निकल रहे हों। उनको एक ऐसा हेलमेट मिल सके जिस पर वे भरोसा कर सकें। हेल्डेन उन राइडर्स के लिए हमारा जवाब है जो रोज़ाना व्यावहारिकता और प्रीमियम डिज़ाइन के साथ वैश्विक स्तर की सुरक्षा का मिश्रण चाहते हैं।

कितनी है कीमत

राइज मोटो की ओर से Reise Moto Helden हेलमेट को पांच रंगों के विकल्प में ऑफर किया गया है जिसमें Black Orange, Black Matte, Black Grey, Black Red और Black Gloss के विकल्प मिलेंगे। इस हेलमेट की बाजार में कीमत 3499 रुपये रखी गई है।

कहानी; ठंड में ठंडा चूल्हा

विजय गर्ग

रामकुमार खाना खाकर थोड़ी देर धूप में बैठा ही था, कि ठेकेदार ने उसे देख लिया।

वह गुस्से में रामकुमार के पास आया। उसे देख कर रामकुमार उठ कर ईंटे उठाने को चल दिया।

उसे देख कर रामकुमार उठ कर ईंटे उठाने को चल दिया। तभी ठेकेदार बोला – ''कहां जा रहा है बे, कब से आराम फरमा रहा था। अब मुझे देख कर काम पर लग गया।''

रामकुमार सकपका गया। वह बोला – ''नहीं मालिक बस अभी खाना खाकर दो मिनट धूप में बैठा था। बहुत ठंड है।''

ठेकेदार ने उसे घूरते हुए कहा – ''अगर धूप ही सेकनी है तो घर जाकर सेक यहां काम करने आता है या धूप सेकने। तेरे आधे दिन के पैसे काटूंगा।''

रामकुमार को बहुत गुस्सा आया लेकिन अपने परिवार के बारे में सोच कर बोला – ''मालिक ऐसा जुल्म न करो बच्चे भूखे मर जायेंगे।''

ठेकेदार को और गुस्सा आ गया – ''अबे मैंने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है। कल के मरते आज मर जायें।''

अब पानी सिर के उपर हो चुका था। रामकुमार ने इधर उधर देखा उसके साथ के सारे मजदूर अपने अपने काम में लगे थे, जैसे किसी ने कुछ सुना ही न हो।

रामकुमार बोला – ''मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोल नहीं तो यही ईंट तेरे सिर में मार दूंगा। चल मैं काम नहीं करता ला मेरा हिसाब कर आधे दिन के पैसे दे।''

ठेकेदार बोला – ''अच्छा मुझे धमकी देता है जा भाग जा नहीं देता पैसे जो करना है कर ले।''

रामकुमार को अपनी गलती का अहसास हो गया। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा।

रामकुमार ने कहा – ''मुझे माफ कर दो पर आधे दिन के पैसे तो दे दो।''

लेकिन ठेकेदार अपनी बात पर अड़ा था। रामकुमार बहुत गिड़गिड़ाया लेकिन ठेकेदार ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। वह थक हार कर वापस घर की ओर चल दिया।

शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी लाजो और उसकी बेटी कन्तो रहते थे। आज जब वह घर पहुंचा तो लाजो ने पूछा – ''क्या हुआ बहुत परेशान हो और इतनी जल्दी काम पे से कैसे आ गये।''

रामकुमार ने कुछ नहीं कहा वह बस इतना बोला – ''कम खत्म हो गया कल से कहीं और काम देखना पड़ेगा।''

वह बाहर पड़ी टूटी सी खाट को धूप में खिसका कर लेट गया। पास ही में कन्तो खेल रही थी।

जब उसका ध्यान अपने पिता पर गया तो वो उनके पास आई – ''बापू तुमने कहा था कल बाजार चलेंगे। आज मैं भी आपके साथ चलूंगी।''

यह सुनकर लाजो भी बाहर निकल आई – ''हांजी आज जल्दी आ गये हो तो घर का राशन लेने चलते हैं। घर में कुछ भी नहीं है पकाने को परसो सामान लाये थे दो दिन चल गया।''

रामकुमार सोच में पड़ गया। फिर वह बोला – ''मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठेकेदार ने बेईमानी कर ली मुझे आज पैसे ही नहीं दिये।''

लाजो सिर पकड़ कर बैठ गई – ''हे भगवान अब क्या करेंगे कहां से खाना पकाउंगी हम तो रह लेंगे लेकिन कन्तो भूखी कैसे रहेगी।''

रामकुमार करवट लेकर लेट गया। उसके पास इस सवाल का कोई जबाब नहीं था। शाम होने लगी तो रामकुमार चारपाई को झोपड़ी के अंदर ले गया और एक पुराना सा कंबल ओढ़ कर लेट गया।

लाजो बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद वह कन्तो को घर का ध्यान रख यह बोल कर कहीं चल दी। पास ही में उसकी एक सहेली रहती थी। वह उसकी झोपड़ी के पास पहुंची। तो वह बाहर ही मिल गई।

लाजो बोली – ''बहन थोड़ी सी मदद कर दो आज उनका काम छूट गया ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिये। घर में खाने को कुछ नहीं है बच्ची के लिये थोड़ा सा खाना दे दो।''

सरिता बोली – ''अरे बहन कोई बात नहीं तुम राशन ले जाओ जो जो सामान चाहिये ले जाओ पका लेना और सब खा लेना।''

लाजो बोली – ''नहीं बहन बस कन्तो के लिये दे दो हम तो भूखे भी रह लेंगे।''

सरिता बोली – ''बहन कब तक भूखे रहोगे अब पता नहीं तेरे आदमी को काम कब मिले उससे कह जरा दिमाग ठंडा रखे नहीं तो रोज चूल्हा ठंडा रहेगा।''

लाजो को बहुत बुरा लगा – ''बहन ऐसी क्या बात हो गई तो तुम ऐसे बोल रही हों।''

सरिता ने राशन का सामान एक थेले में डाला और थैला लाजो को पकड़ाते हुए बोली – ''बहन मैं तेरी सहेली हूं मेरी बात का बुरा मत मान आज तेरे आदमी ने ठेकेदार से लड़ाई कर ली। उसे ईंट मारने की धमकी दी तभी उसने उसे भगा दिया। मेरे आदमी ने बताया। वहां काम खत्म नहीं हुआ है।''

लाजो वहीं बैठ गई – ''हे भगवान अब क्या होगा? ये तो कह रहे थे काम खत्म हो गया। मैंने सोचा ठेकेदार सारे मजदूरों को कहीं और लगवा देगा।''

सरिता बोली – ''बहन हम गरीब लोग हैं हमें तो सबकी सुननी पड़ती है। ठेकेदार मेरे आदमी को भी रोज गाली देता है। लेकिन सब सुनना पड़ता है।''

लाजो कुछ नहीं बोली राशन लेकर सीधे घर आ गई। आज उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खाना बनाया और रामकुमार से कहा – ''चलो खाना खा लो।''

रामकुमार उठ कर बैठ गया और बोला – ''राशन कहां से आया तू तो कह रही थी घर में कुछ नहीं है।''

लाजो को गुस्सा और तेज हो गया वह बोली – ''भीख मांग कर लाई हूं। तुम तो लोगों के ईंट मारो मुझे तो अपनी बच्ची के लिये भीख मांगनी पड़ेगी। सरिता से मांग कर लाई हूं।''

रामकुमार को भी गुस्सा आ गया वह बोला – ''कोई मेरी बच्ची को मरने के लिये बोलेगा तो उसका सिर फाड़ दूंगा।''

लाजो ने यह सुना तो वह पूछने लगी कि क्या बात थी।

रामकुमार ने सारी बात बताई तो वह बोली – ''चलो छोड़ो कल किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाकर काम की बात कर लेना आज का काम तो चल गया लेकिन कल क्या होगा?''

रामकुमार की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी लाचारी और गरीबी पर बहुत शर्मिन्दा था। लाजो उसे समझा रही थी।

रामकुमार बोला – ''हम गांव में कितने सुखी थे। सूखी रोटी मिलती थी। लेकिन पूरे गांव में इज्जत थी। यहां शहर में बेज्जती भी होती है मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं। उपर से महंगाई।''

लाजो बोली – ''मैं तो पहले ही कह रही थी यहीं रहते हैं आप ही को लग रही थी। शहर में जाकर ज्यादा पैसे कमा लेंगे।''

रामकुमार चुपचाप खाना खाकर सो गया। कन्तो ने भी खाना खा लिया था लेकिन लाजो के हल्क से एक निवाला भी नहीं उतरा था।

अगले दिन रामकुमार ने काम ढूंढना शुरू किया लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। वह शाम को घर आया तो पता लगा कन्तो को तेज बुखार है। वह उसे डाक्टर के पास भी नहीं लेजा सकता था। लाजो के पास कुछ पैसे थे तो केमिस्ट से बुखार की गोली ले आया और कन्तो के सिर पर पट्टी रखता रहा।

जैसे तैसे रात गुजरी भूख से दोंनो बेहाल थे। कन्तो का बुखार उतर गया था। लेकिन वह बहुत कमजोर थी।

रामकुमार सुबह उठ कर उसी ठेकेदार के पास पहुंचं गया और बोला – ''मालिक मेरे से बहुत भूल हो गई माफ कर दो वापस काम पर रख लो।''

ठेकेदार बोला – ''नहीं भैया कल तुझे गुस्सा आया और तूने ईंट मार दी तो मैं तो मर जाउंगा। एक काम कर मुनीम जी से अपने आधे दिन के पैसे ले जा और मेरा पीछा छोड़।''

रामकुमार पैसे लेकर घर आया। पैसे लाजो को दिये लाजो कुछ सामान ले आई और कन्तो के लिये थोड़ा सा दूध ले आई।

रामकुमार बोला – ''लाजो चल इन बचे पैसों से गांव चलते हैं। वहां इज्जत की दो रोटी तो मिल ही जाती थीं। कभी भूखे नहीं सोना पड़ा। यहां दिन रात मेहनत करके भी चूल्हा ठंडा पड़ा है।''

लाजो बोली – ''मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। अपना घर अपना ही होता है। इस शहर में इस झोपड़ी में ठंड में पड़े रहते हैं। अब तो चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। चलो चलते हैं।''

सारा सामान बांध कर वे तीनों हमेशा के लिये गांव चल दिये।

एजिंग की जीवविज्ञान

विजय गर्ग

बचपन के दौरान और किशोरावस्था के दौरान, हम में से अधिकांश अपेक्षाकृत अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, हमारी धब्बा मुक्त त्वचा से लेकर हमारे अच्छी तरह से काम करने वाले आंतरिक अंगों तक। हमारे जीवन की इस अवधि में, सेल पुनर्जनन सहजता से होता है। जब कोशिकाएं वृद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो हमारे शरीर स्वाभाविक रूप से चल रही जीवन शक्ति और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कोशिका विभाजन और प्रतिकृति की प्रक्रिया शुरू करते हैं।

जैसे-जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, हमारी कोशिकाएं अधिक से अधिक बार विभाजित होने लगती हैं। जब ऐसा होता है और वे अब नई कोशिकाएं नहीं बना सकते हैं, तो वे सेनेसेंस की स्थिति तक पहुंचते हैं।

लेकिन कामुकता क्या है, बिल्कुल?

आज, हम उम्र बढ़ने के जीव विज्ञान की खोज कर रहे हैं और हमारे शरीर की उम्र कैसे और क्यों है, इसकी बेहतर समझ हासिल करने के लिए इसका संबंध है।

सेनेसेंस और एजिंग संवेदनशीलता और उम्र बढ़ने के बहुत समान अर्थ हैं। 'उम्र बढ़ने' शब्द हमारे स्वास्थ्य में शारीरिक और मानसिक गिरावट सहित पुराने बनने की समग्र प्रक्रिया को शामिल करता है। हालांकि, सेनेसेंस एक सेलुलर स्तर पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो हमारे जीवनकाल में हमारी कोशिकाओं के भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है।

जैसे-जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, अधिक कोशिकाएं विभाजित करने की क्षमता खो देती हैं, और हमारे शरीर में सीसेंट कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इन कोशिकाओं का संचय अक्सर समग्र उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है, झुर्रियों की उपस्थिति से लेकर उम्र से संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों के उद्भव तक।

उम्र बढ़ने के कई कारण हैं? 1900 में, एक नवजात शिशु की औसत जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी। उस दौरान, अधिकांश लोग कैंसर या हृदय रोग जैसे सेनेसेंस के प्रभावों से संबंधित मौतों का अनुभव करने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। बल्कि, संक्रामक रोगों और परजीवी जैसे बाहरी प्रभावों के कारण समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई।

आज के लिए तेजी से आगे, जब औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 76 वर्ष हो गई है। अब, अधिकांश लोग 50 और उससे अधिक उम्र बढ़ने के कई कारणों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं, जो कि शिष्टाचार के सौजन्य से होता है। लेकिन सेनेसेंस होने का क्या कारण है?

नीचे कुछ कारक दिए गए हैं जो हमारी कोशिकाओं को संवेदी बनने के लिए प्रभावित करते हैं:

टेलोमेरे छोटा टेलोमेरेस बार-बार डीएनए अनुक्रम होते हैं जो हमारे गुणसूत्रों के अंत में दिखाई देते हैं। वे प्रत्येक कोशिका के लिए एक जैविक घड़ी के रूप में कार्य करते हैं, एक कोशिका के विभाजित होने की संख्या की गिनती करते हैं।

हर बार जब एक सेल एक नया सेल बनाने के लिए विभाजन से गुजरता है, तो इसका टेलोमेरे छोटा हो जाता है। आखिरकार, गुणसूत्र का टेलोमेरे आगे विभाजित करने के लिए बहुत छोटा हो जाता है, जो कोशिका को सेनेसेंस की स्थिति में ट्रिगर करता है।

ऑक्सीडेटिव क्षति हर दिन कार्य, जैसे श्वास और गतिमान, अत्यधिक अस्थिर और प्रतिक्रियाशील अणु बनाते हैं जिन्हें हमारे शरीर में मुक्त कण कहा जाता है। सौभाग्य से, हमारे सिस्टम एंटीऑक्सिडेंट का उपयोग उन्हें बेअसर करने के लिए करते हैं, उन्हें हमें नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं।

हालांकि, यूवी विकिरण और प्रदूषण जैसे बाहरी कारक हमारे अंदर मुक्त कणों की अधिकता पैदा कर सकते हैं, जिससे मुक्त कणों और एंटीऑक्सीडेंट के बीच नाजुक संतुलन बाधित हो सकता है। यह असंतुलन, जिसे ऑक्सीडेटिव तनाव के रूप में जाना जाता है, हमारी कोशिकाओं और डीएनए में अणुओं को नुकसान पहुंचा सकता है, टेलोमेरेस को छोटा कर सकता है और सेल में कुछ रास्तों को सक्रिय कर सकता है जो सेनेसेंस का कारण बनते हैं।

एजिंग के रूप में संवेदनशीलता के भौतिक प्रभाव जैसे-जैसे आप की उम्र बढ़ाते हैं, अधिक कोशिकाएं सेनेसेंस तक पहुंचती हैं, उम्र बढ़ने के कई पहलुओं का अनुभव करने की संभावना बढ़ जाती है, जिनमें शामिल हैं:

महीन रेखाएँ और झुर्रियाँ आंखों की रोशनी और सुनवाई में कमी संज्ञानात्मक गिरावट आयु से संबंधित रोग, जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और ग्लूकोमा सौभाग्य से, जीवन शैली कारक उस दर में एक भूमिका निभाते हैं जिस पर आप उम्र! आप निम्नलिखित प्रथाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके सेलुलर सेनेसेंस की प्रक्रिया को धीमा करने में सक्षम हो सकते हैं:

स्वस्थ वसा, प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर संतुलित आहार लेना। नियमित व्यायाम में संलग्न। पर्याप्त मात्रा में नींद प्राप्त करना। संभावित हानिकारक यूवी किरणों के लिए अपने जोखिम को सीमित करने के लिए सनस्क्रीन पहनना। पढ़ने, पहेली और परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क में रखने जैसी गतिविधियों के साथ अपने मस्तिष्क को उत्तेजित करना। युएफ से ग्रेजुएट क्रेडेंशियल के साथ एजिंग में अपना करियर शुरू करें पिछले सौ वर्षों में, औसत मानव जीवनकाल दोगुना से अधिक हो गया है, जो उम्र बढ़ने के क्षेत्र में पेशेवरों की बढ़ती मांग को उजागर करता है। जेरोन्टोलॉजी, उम्र बढ़ने का अध्ययन, मुख्य रूप से पुराने वयस्कों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस अनुशासन की नींव बनाता है।

अपने देश इंडिया का असली नाम है भारतवर्ष इसमें क्या है 'वर्ष' का मतलब

विजय गर्ग

इंडिया का असली नाम भारतवर्ष है। प्राचीन काल में इसे इसी नाम से जानते थे। सिकंदर जब यहां आया तो उसने हमारे देश को इंडिका कहा। अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा। फारस की ओर से आने वालों ने इसे हिन्दुस्तान कहा। मुगलों ने भी इसे हिंदुस्तान का नाम दिया। हम सभी अपने देश को भारत के नाम से बुलाते हैं। अक्सर इसे भारतवर्ष भी कहा जाता है। क्या आपको मालूम है कि भारत के आगे वर्ष क्यों लगाया जाता है।

स्वतंत्रता के बाद, 1950 में भारत के संविधान में देश का आधिकारिक नाम भारत और India दोनों को मान्यता दी गई। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है: "भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा।ₓ इस प्रकार, "भारत" नाम को आधिकारिक रूप से अपनाया गया और "भारतवर्ष" का उपयोग धीरे-धीरे औपचारिक और साहित्यिक बोलचाल तक सीमित हो गया। लेकिन देश का असल नाम भारतवर्ष ही है और इसमें वर्ष का क्या मतलब है, ये आप समझ ही गए होंगे।

भारतवर्ष देश के बारे में क्या बताता है।

भारतवर्ष ना केवल हमारे देश की भौगोलिक सरहदों के बारे में बताता है बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को भी समेटे हुए है। यह नाम भारतीय सभ्यता की गहरी जड़ों और इसके गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। लेकिन "भारतवर्ष" में ₹वर्ष" का क्या अर्थ है ? और समय के साथ यह नाम केवल ₹भारतₓ क्यों रह गया ?

भारतवर्ष का नाम कैसे आया

भारतवर्ष" शब्द दो भागों से मिलकर बना है: भारत और वर्ष । ₹भारतₓ शब्द का संबंध प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पौराणिक कथाओं से है। इसकी उत्पत्ति के लिए दो प्रमुख बातें कही जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, "भारत" नाम का संबंध चक्रवर्ती सम्राट भरत से है, जो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। यह कथा महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञानशाकुंतलम् और महाभारत में कही गई है। भरत एक महान शासक थे, जिन्होंने विशाल भू-भाग पर शासन किया। उनके नाम पर इस क्षेत्र को "भारतवर्ष" कहा गया। जैन परंपरा में ₹भारतₓ नाम का संबंध प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ पुत्र भरत से है। जैन ग्रंथों के अनुसार, ऋषभनाथ ने अपने पुत्र भरत को इस क्षेत्र का शासक बनाया और उनके नाम पर इसे "भारतवर्ष" कहा गया। आदिपुराण जैसे जैन ग्रंथों में इसका जिक्र है।

वर्ष का मतलब क्या है

संस्कृत में "वर्ष" शब्द का अर्थ है " भाग" या "विभाग"। प्राचीन भारतीय भूगोल में, पृथ्वी को कई ₹वर्षों" या क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से एक जंबूद्वीप का हिस्सा था। जंबूद्वीप को नौ ₹वर्षोंₓ में बांटा गया था, और इनमें एक वर्ष यानि एक भाग को

भारतवर्ष कहा गया। "वर्षₓ का अर्थ भौगोलिक क्षेत्र या खंड से है। प्राचीन ग्रंथों जैसे पुराणों (विशेष रूप से विष्णु पुराण और भागवत पुराण) में भारतवर्ष को जंबूद्वीप के दक्षिणी भाग के रूप में बताया गया है। इस प्रकार, भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ है "भरत के शासन वाला क्षेत्रₓ या ₹भरत का देश₹। यह नाम न केवल एक भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को भी जाहिर करता है।

ग्रंथ भारतवर्ष के बारे में क्या कहते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भारतवर्ष का उल्लेख एक पवित्र और समृद्ध क्षेत्र के रूप में किया गया है। विष्णु पुराण में भारतवर्ष को कर्मभूमि कहा गया है, जहां व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह सभ्यता, धर्म, दर्शन और संस्कृति का केंद्र भी था। महाभारत में भारतवर्ष का उल्लेख एक विशाल और एकीकृत क्षेत्र के रूप में किया गया है, जिसमें हिमालय से लेकर दक्षिणी समुद्र तक का क्षेत्र शामिल था। पुराणों में भारतवर्ष को जंबूद्वीप के नौ खंडों में एक के रूप में बताया गया है। इसमें गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां और हिमालय, विंध्य जैसे पर्वत शामिल हैं। मनुस्मृति में भारतवर्ष को आर्यावर्त के रूप में भी बताया गया है।

क्या थीं भारतवर्ष की भौगोलिक सीमाएं

प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, भारतवर्ष की सीमाएं हिमालय से लेकर दक्षिणी सागर तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक थीं। समय के साथ "भारतवर्ष" का नाम संक्षिप्त होकर केवल ₹भारतₓ रह गया। भारत का इतिहास विभिन्न राजवंशों, साम्राज्यों और विदेशी शासनों से भरा पड़ा है। मौर्य, गुप्त, मध्यकालीन राजपूत, मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र को विभिन्न नामों से जाना गया। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को India (इंडिया) के नाम से संबोधित किया, जो ग्रीक और लैटिन शब्द Indus (सिंधु नदी) से लिया गया था।

एजिंग के रूप में संवेदनशीलता के भौतिक प्रभाव जैसे-जैसे आप की उम्र बढ़ाते हैं, अधिक कोशिकाएं सेनेसेंस तक पहुंचती हैं, उम्र बढ़ने के कई पहलुओं का अनुभव करने की संभावना बढ़ जाती है, जिनमें शामिल हैं: महीन रेखाएँ और झुर्रियाँ आंखों की रोशनी और सुनवाई में कमी संज्ञानात्मक गिरावट आयु से संबंधित रोग, जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और ग्लूकोमा सौभाग्य से, जीवन शैली कारक उस दर में एक भूमिका निभाते हैं जिस पर आप उम्र! आप निम्नलिखित प्रथाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके सेलुलर सेनेसेंस की प्रक्रिया को धीमा करने में सक्षम हो सकते हैं:

स्वस्थ वसा, प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर संतुलित आहार लेना। नियमित व्यायाम में संलग्न। पर्याप्त मात्रा में नींद प्राप्त करना। संभावित हानिकारक यूवी किरणों के लिए अपने जोखिम को सीमित करने के लिए सनस्क्रीन पहनना। पढ़ने, पहेली और परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क में रखने जैसी गतिविधियों के साथ अपने मस्तिष्क को उत्तेजित करना। युएफ से ग्रेजुएट क्रेडेंशियल के साथ एजिंग में अपना करियर शुरू करें पिछले सौ वर्षों में, औसत मानव जीवनकाल दोगुना से अधिक हो गया है, जो उम्र बढ़ने के क्षेत्र में पेशेवरों की बढ़ती मांग को उजागर करता है। जेरोन्टोलॉजी, उम्र बढ़ने का अध्ययन, मुख्य रूप से पुराने वयस्कों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस अनुशासन की नींव बनाता है।

जीवित रहें पुस्तकालय

विजय गर्ग

किसी समाज की सभ्यता और संवेदनशीलता का पैमाना केवल उसकी भौतिक प्रगति से नहीं, बल्कि उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना से भी मापा जाता है। यह चेतना कहां विकसित होती है ? क्या केवल विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ? या फिर केवल घर की चारदीवारी में ? नहीं, यह चेतना उस सार्वजनिक स्थान पर भी आकार लेती है, जहां विचार स्वतंत्र होते हैं, जिज्ञासाएं

पूरित होती हैं और ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती । वह स्थान है सार्वजनिक पुस्तकालय ।

मनुष्य के विकास का इतिहास मूलतः ज्ञान और जानकारी की खोज का इतिहास है। सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य ने जानकारी को संरक्षित करने और साझा करने के विविध प्रयास किए हैं गुफाओं की चित्रकला से लेकर 'डिजिटल आर्काइव' तक। इस संदर्भ में पुस्तकालयों की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण रही है। पुस्तकालय ज्ञान के भंडार से बढ़कर मानवता की सामूहिक स्मृति और विकास की धुरी हैं।

विचार और अधिकार

संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि 'प्रत्येक व्यक्ति को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में सूचना और विचारों को बिना किसी सीमाओं के प्राप्त करने, ग्रहण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।' यह अधिकार तभी सार्थक होता है, जब समाज में ऐसे संस्थान हों जो सबको समान रूप से ज्ञान तक पहुंच प्रदान करें। सार्वजनिक पुस्तकालय इस अधिकार की भौतिक अभिव्यक्ति हैं। जब हम सार्वजनिक पुस्तकालयों की बात करते हैं, तो हम उस अधिकार की भी बात कर रहे होते हैं जो हर मनुष्य को सूचना, शिक्षा और आत्मविकास के लिए प्राप्त होना चाहिए ।

पुस्तकालय विचारों की खान होते हैं, जहां हर आयु, जाति, वर्ग और पृष्ठभूमि का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है और अपने बौद्धिक क्षितिज का विस्तार कर सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय लोकतंत्र के उन मौन स्तंभों में से एक हैं, जहां सूचना की समता संभव होती है। अमीर हो या गरीब, पढ़ा-लिखा हो या ज्ञान की शुरुआत करने वाला हर व्यक्ति पुस्तकालय में समान अधिकार के साथ प्रवेश करता है। यही समानता किसी समाज

को भीतर

से मजबूत करती है।

जब समाज में शिक्षा की पहुंच बढ़ती है, तो उसे पोषण देने के लिए ऐसे मंचों की आवश्यकता होती है जो औपचारिक शिक्षा से आगे जाकर जिज्ञासा को जीवित रखें। पुस्तकालय वही मंच है, जहां पाठ्यक्रम की सीमाएं टूटती हैं और पाठक अपनी गति और रुचि के अनुसार सीखने लगता है। वहां कोई परीक्षा नहीं होती, कोई अंक नहीं दिए जाते, फिर भी सीखने की प्रक्रिया अधिक सजीव और आत्मीय होती है। यह आत्म- प्रेरित अध्ययन किसी भी राष्ट्र की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा देता है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि वे सामाजिक एकता के प्रतीक होते हैं। वे

विचारों की बहुलता को स्वीकार करते हैं और विभिन्न मतों को एक ही छत के नीचे सह-अस्तित्व प्रदान करते हैं। जहां समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, वहां पुस्तकालय जैसे स्थान एक शांतिपूर्ण संवाद की संभावना रखते हैं। अलमारी के एक ही खाने में गांधी और

मार्क्स की किताबें मिल सकती हैं, तुलसी और कबीर साथ-साथ मिल सकते हैं और यही विविधता हमें सहिष्णुता सिखाती है।

ज्ञान का विवेक

तकनीक के इस युग में यह तर्क दिया जा सकता है कि जब सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है ! यह भूलना नहीं चाहिए कि इंटरनेट जानकारी तो देता है, पर संदर्भ और विवेक के साथ ज्ञान नहीं देता। पुस्तकालय एक संरचित और विश्वसनीय ज्ञान का भंडार है, जहां किताबों की उपस्थिति और उनका चयन एक विचारशील प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसके अलावा, डिजिटल पहुंच आज भी अनेक लोगों के लिए एक विशेषाधिकार है, जबकि पुस्तकालय सार्वजनिक और समावेशी होते हैं।

पुस्तकालयों का महत्त्व केवल बौद्धिक नहीं, भावनात्मक और सांस्कृतिक स्तर पर भी है। कितने ही लोगों के लिए पुस्तकालय जीवन की कठिनाइयों में एक आश्रय बनता है। वहां की शांति, किताबों की गंध और पढ़ते हुए समय के रुक जाने का अहसास - यह सब एक

मानसिक सुकून देता है जो शायद किसी और स्थान पर नहीं मिलता। किसी किशोर के लिए जो घर में पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण नहीं पा सकता, पुस्तकालय एक नई दुनिया खोल देता है। किसी वृद्ध के लिए, जो अकेलापन महसूस करता है, वहां का माहौल जीवंतता का अनुभव कराता है ।

समझ का निवेश

आज जब हम शहरीकरण और डिजिटल विकास के नाम पर जगह-जगह माल और सिनेमाघर बना रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि हम पुस्तकालयों को भी उतना ही महत्त्व दें। यह केवल भवनों की बात नहीं है, यह सोच की बात है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में निवेश करना एक दीर्घकालिक निवेश है। ऐसा निवेश जो आने वाली पीढ़ियों को सोचने समझने और बेहतर समाज गढ़ने की शक्ति देता है। यह एक ऐसी विरासत है जिसे बनाए रखना, बढ़ाना और प्रसारित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को केवल एक परंपरागत संस्था समझने की भूल न की जाए। वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे. शायद और भी अधिक । समाज की आत्मा को अगर कभी पढ़ना हो, तो वह उसके पुस्तकालयों की अलमारियों में छिपी पड़ी होती है। वहां मौजूद किताबें मनुष्यता के सबसे सुंदर स्वप्नों, विचारों और अनुभवों की अभिव्यक्ति होती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने सार्वजनिक पुस्तकालयों को न केवल संरक्षित करें, बल्कि उन्हें जीवंत, समृद्ध और समावेशी बनाएं. क्योंकि जहां पुस्तकालय फलते-फूलते हैं, वहीं समाज भी विचारशील, उदार और प्रगतिगामी बनता है।

(विश्वविद्यालय: शिक्षा का मंदिर या जाति की प्रयोगशाला?)

हमारी जाति एचएयू: हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन और जातिगत अन्याय के खिलाफ उठती आवाज

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू), हिसार – देश के प्रतिष्ठित कृषि संस्थानों में गिना जाता है। पर आज यह संस्थान छात्रों के लिए जातिगत अपमान और प्रशासनिक चुप्पी का केंद्र बन गया है। ₹हमारी जाति एचएयू₹ यह नारा केवल नारा नहीं रहा, यह छात्रों की पहचान, आत्मसम्मान और प्रतिरोध की आवाज बन चुका है। एक छात्र ने सवाल किया: ₹हम शिकायत करें तो क्या पहले अपनी जाति साबित करनी होगी?"

✍ प्रियंका सौरभ

"बताइए, कौन-सा खून किस जाति का है?₹ यह सवाल केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि एचएयू (हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय), हिसार में जारी छात्र आंदोलन की आत्मा है। यह उन विद्यार्थियों की पुकार है जो शिक्षा के मंदिर में जातिगत भेदभाव और सत्ता की चुप्पी के खिलाफ लड़ रहे हैं।

एचएयू के छात्र पिछले 9 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और समिति की चुप्पी उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। अब यह आंदोलन केवल प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ नहीं, बल्कि जातिवाद की संस्थागत संरचना के विरुद्ध हो चुका है।

एचएयू: एक प्रतिष्ठित संस्थान, एक गहरी पीड़ा

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) को देशभर में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। पर आज वही संस्थान जाति के कीचड़ में लिपटा हुआ दिख रहा है।

छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जातिगत टिप्पणी की गई, और जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो न सिर्फ उन्हें टालने की कोशिश की गई, बल्कि उन्हें ही जाति के सवालों में उलझा दिया गया।

₹हमारी जाति एचएयू₹ – प्रतिरोध का एक नारा

धरने में एक छात्र का हाथ में पकड़ा पोस्टर अब पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बन चुका है – ₹हमारी जाति एचएयू₹। यह नारा सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक वैचारिक प्रतिरोध है।

यह कह रहा है कि छात्रों की जाति न तो उनके उपनाम से तय होगी, न ही जन्म से, बल्कि उनके संस्थान, उनके ज्ञान और उनकी चेतना से होगी।

छात्रों के सवाल, समिति की चुप्पी

जब प्रशासन की तरफ से एक समिति छात्रों से बातचीत के लिए आई, तो उन्होंने पहले सुझाव दिए। लेकिन छात्रों का सीधा और स्पष्ट उत्तर था – ₹पहले हमारे सवालों का जवाब दो₹।

छात्रों ने पूछा:

हमें जाति क्यों पूछी गई?₹

कोब्स-सा खुद किस जाति का था?₹

हम शिकायत करें तो क्या हमें पहले अपनी जाति साबित करनी होगी?₹

लेकिन समिति इन प्रश्नों पर मौन रही। छात्रों ने इस चुप्पी को सत्ता की स्वीकृति बताया — और ये मौन उस जातिगत मानसिकता की गूंगी पुष्टि बन गया जो वर्षों से उच्च शिक्षा संस्थानों में पलती रही है।

आंदोलन की विशेषताएँ: भूख हड़ताल की चेतावनी और मानवाधिकार आयोग से संपर्क

छात्रों ने अब सांकेतिक भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें स्पष्ट उत्तर और न्याय नहीं मिलता, वे पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है, जिससे यह आंदोलन अब न केवल एचएयू परिसर का मामला रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संकट का रूप ले चुका है।

-प्रियंका सौरभ, रिसर्च स्कॉलर इन पॉलिटिकल साइंस, हरियाणा

जातिवाद का संस्थानीकरण – एक खतरनाक प्रवृत्ति

आज का भारत तकनीकी, आर्थिक और डिजिटल रूप से जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, सामाजिक मानसिकता उतनी ही जड़ हो रही है। जब देश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय जातिवादी मानसिकता के अधीन काम करता है, तो यह न केवल शिक्षा की गरिमा को चोट पहुँचाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सोचने के अधिकार को भी छीनता है।

शिक्षा संस्थानों में जातिगत टिप्पणियाँ अब अपवाद नहीं, एक संस्थागत चलन बन चुकी हैं। यह चलन जब तक नहीं टूटेगा, तब तक न रोहित वेमुला का सवाल रुकेगा, न एचएयू के छात्रों की भूख।

कृषि विश्वविद्यालय में जाति – सबसे विडंबनापूर्ण सत्य

कृषि भारत की रीढ़ है, और कृषि शिक्षा संस्थान किसानों के बेटों-बेटियों के सपनों का केंद्र। पर जब वही संस्थान उन्हें उनकी जाति की हैसियत से तोलने लगे, तो यह सिर्फ शिक्षा की असफलता नहीं, यह पूरे ग्रामीण भारत की पीड़ा की प्रतीक बन जाती है।

कई छात्र स्वयं पिछड़े या दलित समुदायों से आते हैं। उनके लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो उन्हें खेत की मेड़ से वैज्ञानिक प्रयोगशाला तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि संस्थान ही उन्हें ₹तू कौन जात?₹ जैसे सवालों में उलझा दे, तो यह शुद्ध अन्याय है।

छात्रों को मिला सामाजिक समर्थन

इस आंदोलन में सिर्फ छात्र ही नहीं, किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ पूर्व छात्र, और यहां तक कि विधायक और जन प्रतिनिधि भी छात्रों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। यह दिखाता है कि यह लड़ाई अब अकेली नहीं है।

छात्रों ने यह साफ कर दिया है कि अगर उनकी आवाज़ दबाई गई, तो वे शांत नहीं बैठेंगे। ₹हमारी जाति एचएयू₹ अब नारा नहीं, चेतावनी बन चुका है।

प्रशासन का असफल संवाद

एचएयू प्रशासन इस पूरे मामले में अपनी भूमिका को लेकर असहज और असमर्थ दिख रहा है। कुलपति की चुप्पी, समिति के जवाब न देने की नीति, और केवल औपचारिकता निभाने वाले अधिकारियों ने छात्रों की नाराजगी को और गहरा कर दिया है।

प्रशासन को यह समझना चाहिए कि ₹संवाद₹ कोई अनुग्रह नहीं, लोकतंत्र की अनिवार्यता है।

यदि छात्र सवाल पूछ रहे हैं, तो प्रशासन का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी से उत्तर दे, न कि उन्हें 'अशिष्ट' कहकर खारिज करे।

अब आगे क्या होना चाहिए?

1. स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कमेटी बनाई जाए जिसमें छात्र प्रतिनिधि भी शामिल हों।
2. जातिगत टिप्पणी करने वाले अधिकारी पर तत्काल कार्यवाही हो।
3. विश्वविद्यालय में जाति-निरपेक्ष संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ।
4. छात्र संघ को वैधानिक मान्यता और स्वतंत्रता दी जाए।
5. शिक्षा विभाग और सरकार को एचएयू जैसे संस्थानों की जवाबदेही तय करनी होगी।

एचएयू से देशभर के विश्वविद्यालयों तक फैलती चेतना

यह आंदोलन केवल एचएयू का नहीं है। यह उस नवीन छात्र चेतना का प्रतीक है जो अब जाति, भ्रष्टाचार और संस्थागत अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही है।

यह वही चेतना है जो रोहित वेमुला की चुप्पी से जन्मी,

जेएनयू की दीवारों पर लिखी गई,

और अब एचएयू के पोस्टरों पर 'हमारी जाति एचएयू' बनकर चमक रही है।

छात्रों की मांगें कोई असंभव बातें नहीं हैं — वे सिर्फ न्याय, समानता और गरिमा की उम्मीद कर रहे हैं।

और यदि एक कृषि विश्वविद्यालय में छात्र समानता नहीं पा सकते, तो कृषि का भविष्य और समाज की आत्मा — दोनों ही खतरे में हैं।

एचएयू को अब तय करना होगा:

वह इतिहास में किस रूप में दर्ज होना चाहता है –

एक जातिवादी संस्थान के रूप में,

या एक सुधरते हुए लोकतांत्रिक विश्वविद्यालय के रूप में।

निर्णय उसके हाथ में है।

लेकिन आवाज अब छात्रों के साथ है।

और वह आवाज अब दबने वाली नहीं।

ना पूछो उनका पता हो गए लापता..!

इंद्रायणी नदी में देखने आए नजारा,
ना पूछो उनका पता हो गए लापता।
पुणे के मावल – कुंडमाला इलाके में,
हादसा कईयों को बहा गया घापे में।
यहाँ तीस साल पुराना पुल ढह गया,
सौभाग्शाली रहा जो ज़िन्दा रह गया।

इंद्रायणी नदी में देखने आए नजारा,
ना पूछो उनका पता हो गए लापता।
भारी बारिश एवं तेज था जल प्रवाह,
वीडियो बनानेवाले बनते खुदागवाह।
उस वक्त 100 लोग पुल पर मौजूद,
क्या? पता इनमें किसका रहा वजूद।

इंद्रायणी नदी में देखने आए नजारा,
ना पूछो उनका पता हो गए लापता।
जर्जर पुल पे ही क्यों वीकेंड मनाना,
शासन ने बंद रखा यहां आना-जाना।
30साल पुराना लोहा कितना चलता,
नदी का बहाव हर साल खूब गलता।

संजय एम तराणेकर

वाराणसी पहली बारिश में ही खुलीं सीवर की साफ-सफाई और रोड पर गड्ढे की पोल वसीम अहमद

परिवहन विशेष न्यूज

वाराणसी। वैसे तो बारिश से पहले सीवर लाइन और रोड पर गड्ढे भरने का काम जोरों पर चल रहा है मगर ऐसा हाल बजरडीहाँ क्षेत्र का की नगर निगम द्वारा जगह जगह सीवर लाइन ध्वस्त और सीवर जाम की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ ऐसे में सवाल उठता हैं वाराणसी मेयर अशोक कुमार तिवारी द्वारा कहा गया था कि वाराणसी के सभी वार्डो में सीवर स्ट्रीट लाइट जो खराब है या बंद है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए ताकि राह चल रहे लोगों को दिक्कत ना हो

बजरडीहा क्षेत्र के रहने वाले वसीम अहमद ने मिडिया को बताया कि बजरडीहाँ क्षेत्र वार्ड नंबर 27 में सीवर ओवरफ्लो से जनता काफी परेशान हैं और बिजली के खंभे पर लगा लाइट बंद है और कितने खंबों पर लाइट्स ही नहीं लगीं हैं जिससे रात में आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

राहुल गांधी के 'मिशन बिहार' को बड़ा झटका- अब कांग्रेस क्या करेगी?

संतोष कुमार पाठक

बिहार में वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सबसे बड़े दल के तौर पर राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जबकि कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आई थी। सीपीआई-माले 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी।

कांग्रेस पार्टी को देशभर में मजबूत बनाने के अभियान में जुटे राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वर्ष 2025 में वह अब तक कुल मिलाकर पांच बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। अपने इन दौरे के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार के दलित मतदाताओं, अन्य पिछड़ी जाति के लोगों और अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं के साथ संवाद कर, उन्हें साधने की कोशिश की। पार्टी संगठन को धार और नई रफ्तार देने के लिए उन्होंने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों तक को बदल दिया।

लेकिन राहुल गांधी के इस 'मिशन बिहार' को उनके अपने ही सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा झटका दे दिया है। लालू यादव के फॉर्मूले ने कांग्रेस पार्टी को बेचैन कर दिया है। कांग्रेस 2020 की तरह इस बार भी 70 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहती है लेकिन राजद ने इतनी सीटें देने से साफ-साफ इनकार कर दिया है। यानी अब यह तय हो गया है कि विपक्षी महागठबंधन में कांग्रेस को इस बार 2020 की तरह 70 सीटें नहीं मिलेगी। गठबंधन और सीटों को लेकर होने वाली बैठकों की अध्यक्षता भले ही तेजस्वी यादव कर रहे हो लेकिन पर्दे के पीछे से सब कुछ लालू यादव ही तय कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, राजद ने यह साफ कर दिया है कि राजनीतिक दलों की संख्या और क्षमता के आधार

पर गठबंधन में कांग्रेस को लगभग 53 सीटें ही मिल सकती है।

बिहार में वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सबसे बड़े दल के तौर पर राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जबकि कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आई थी। सीपीआई-माले 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी इस बार विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी की पार्टी को सीट बंटवारे में एडजस्ट करने की चुनौती है वहीं लेफ्ट फ्रंट के दल खासकर सीपीआई-माले सीट बढ़ाने की मांग को लेकर अड़ गया है। ऐसे में लालू यादव भी अपनी पार्टी के कोटे को घटाने पर तैयार हो गए हैं। लेकिन वो किसी भी कीमत पर 140 से कम पर जाने को तैयार नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के सामने जो पहला फॉर्मूला रखा है उसके तहत आरजेडी 144 की बजाय 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार की तरह ही इस बार भी सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें ही दी जाएगी। लेकिन सीपीआई-माले को 6 सीटें बढ़ाकर 25 सीटें दी जा सकती है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 15 सीटों पर लड़ाया जाएगा। वहीं पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को इस बार 53 सीटों के आसपास ही संतोष करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में 2-3 सीटों का हेरफेर किया जा सकता है।

लेकिन अगर आने वाले दिनों में पशुपति पारस, असदुद्दीन ओवैसी, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव को भी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन में शामिल किया गया तो फिर सभी दलों को त्याग करना पड़ेगा। ऐसे हालात में, कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 45-46 सीटें ही आ पाएंगी। यानी लालू यादव के पहले फॉर्मूले के तहत कांग्रेस को 53-55 और दूसरे फॉर्मूले के तहत सिर्फ 45-46 सीटें ही मिल सकती है।

आपको याद दिला दें कि, वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राजद मुखिया लालू यादव जेल में थे। यह आरोप लगाया जाता है कि लालू यादव के जेल में रहने का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने तेजस्वी यादव पर दबाव डालकर गठबंधन में 70 सीटें झटक ली। लेकिन 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। लालू यादव और तेजस्वी यादव सहित विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं का यह मानना है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण ही बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए थे।

लालू यादव 2020 के विधानसभा चुनाव के समय पर जेल में थे लेकिन इस बार बाहर है और सीट बंटवारे के अपने फॉर्मूले पर अडिग है।

राजद के इस फॉर्मूले ने कांग्रेस नेताओं को दुविधा की स्थिति में डाल दिया है। अब गेंद राहुल गांधी के पाले में है कि वह इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं या सीधे लालू यादव से बात करके कांग्रेस के कोटे की सीटों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें। हालांकि बिहार में कांग्रेस के कई नेता दबी जुबान में एक तीसरे विकल्प की बात भी कर रहे हैं। तीसरा विकल्प यानी राहुल गांधी बिहार में अन्य छोटे-छोटे दलों को साथ लेकर तीसरा मोर्चा बनाए और बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ जाएं।

– संतोष कुमार पाठक
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं।

दुनिया में कोई फ्री में नहीं खिलाता, व्हाइट हाउस में ट्रंप की रोटी खाते ही मुनीर को यह बात समझ आ गयी

नीरज कुमार दुबे

जहां तक ट्रंप और मुनीर के लंच की बात है तो बताया जा रहा है कि पहला निवाला मुंह में डालते ही मुनीर के होश उड़ गये क्योंकि वह कट्टरपंथी स्वभाव के हैं इसलिए उन्हें यह बात रास नहीं आई कि वह ईरान का साथ देने की बजाय इजराइल को अपना मिशन पूरा करते हुए देखें।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ दोपहर का भोज करके पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान में सरकार नहीं बल्कि सेना ही असली ताकत रखती है। ट्रंप ने जिस तरह से असीम मुनीर को खाना खिलाते समय कहा कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है उससे यह भी संकेत मिले कि अमेरिकी राष्ट्रपति के मन में कुछ बड़ा चल रहा है। हम आपको बता दें कि ईरान पर हमला करने की तैयारी कर चुका अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसकी मदद करे। हम आपको याद दिला दें कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन को उखाड़ने के लिए भी अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना बेस बनाया था। चूंकि ईरान की सीमाएं भी पाकिस्तान के साथ लगती हैं इसलिए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान एक बार फिर उसे अपना बेस वहां बनाने दे ताकि उसके लड़ाकू विमान वहीं से उड़ान भर सकें। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान में इस बात की इजाजत वहां की सरकार नहीं बल्कि सेना ही दे सकती है इसलिए मुनीर को लंच पर बुलाया गया।

इसके अलावा इजराइल भी चाहता है कि ईरान को किसी भी मुस्लिम देश की मदद नहीं मिले, इसके लिए उसने अमेरिका से पाकिस्तान को समझाने के लिए कहा था। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं और हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान पर हुए इजराइली हमलों की निंदा की है इसलिए ट्रंप यह सुनिश्चित कर रहे थे कि पाकिस्तान ईरान की मदद के लिए आगे नहीं आये। इसके अलावा ट्रंप का एक और गेम प्लान यह था कि वह मुनीर को लंच कराने के दौरान उनकी भेंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवा दी जाये लेकिन मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह चाल समझ गये थे इसलिए उन्होंने कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका में कुछ समय रुकने का उनका आग्रह ठुकरा दिया था। मोदी समझ गये थे कि यदि ट्रंप ने अचानक उनकी और मुनीर की भेंट करवा कर दुनिया के सामने फिर से यह दावा कर दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवा दी है तो उनके लिए घरेलू राजनीतिक मोर्चे पर नई मुश्किल खड़ी हो जायेगी।

जहां तक ट्रंप और मुनीर के लंच की बात है तो बताया जा रहा है कि पहला निवाला मुंह में डालते ही मुनीर के होश उड़ गये क्योंकि वह कट्टरपंथी स्वभाव के हैं इसलिए उन्हें यह बात रास नहीं आई कि वह ईरान का साथ देने की बजाय इजराइल को अपना मिशन पूरा करते हुए देखें। मुनीर को ट्रंप की रोटी खाते ही यह बात समझ आ गयी कि दुनिया में कोई भी फ्री में कुछ नहीं खिलाता। वैसे भी ट्रंप राजनीतिज्ञ कम, व्यापारी ज्यादा हैं और उन्हें पता है कि पाकिस्तान के किसी भी सेनाध्यक्ष को मुंहमांगी

कीमत देकर आसानी से खरीदा जा सकता है। यही काम ट्रंप ने किया और मुनीर को अपने पाले में कर लिया। वैसे, अमेरिकी राजनीति के इतिहास में यह दुर्लभ ही नहीं बल्कि अभूतपूर्व घटना है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेशी सैन्य प्रमुख को लंच पर बुलाए। हालांकि अयूब खान, जिया-उल-हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे पाकिस्तानी सैन्य नेताओं ने अतीत में अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने यह मुलाकात तब की थी जब वे सैन्य तख्तापलट के बाद पाकिस्तान के नेता बन गए थे। हम आपको यह भी बता दें कि ज़िया-उल-हक और मुशर्रफ ने भी अमेरिका से अरबों डॉलर की सैन्य सहायता और अनुदान प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान को एक ₹किराए की सेना₹ में बदल दिया था।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में भी कहा गया है कि ट्रंप की इस पहल को मुनीर को पाकिस्तान का वास्तविक नेता मानने के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका ईरान में अपने संभावित हमलों के लिए मुनीर का समर्थन प्राप्त करना चाहता है। इसके साथ ही अमेरिका और इज़राइल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान इस्लामी दुनिया में अलग-थलग रहे और उसे पाकिस्तान का समर्थन नहीं मिले। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप की अजीबो-गरीब नीतियों को देखते हुए, यह भी संभव है कि मुनीर को चेतावनी दी गई हो कि अगर इस्लामाबाद ने ईरान का समर्थन किया तो परिणाम भुगतने होंगे। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की है और उन्हें ₹ईरान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन₹ और ₹अनुचित तथा अवैध आक्रामकता₹ बताया है।

एक रोचक तथ्य यह भी है कि वैसे तो मुनीर कट्टर इस्लामवादी माने जाते हैं, मगर उनके बारे में अमेरिका में रहने वाले इमरान खान की पीटीआई पार्टी के समर्थकों का आरोप है कि वह इज़राइल समर्थक हैं और अमेरिका-इज़राइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान एकमात्र इस्लामी परमाणु शक्ति बना रहे। हम आपको बता दें कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने ही सबसे पहले मुनीर की अमेरिका में गुप्त यात्रा का खुलासा किया था और आरोप लगाया था कि उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में एक इज़राइल समर्थक लॉबी समूह AIPAC की बैठक में भाग लिया। उन्होंने उनके अमेरिकी सहयोगी साजिद तारार को ₹इज़राइल का कट्टर समर्थक और फिलिस्तीनी व ईरानी मुसलमानों का दुश्मन₹ बताया था।

जहां तक ट्रंप और मुनीर के लंच के बाद आये अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ₹मुझे पाकिस्तान से प्यार है₹। साथ ही उन्होंने यह दावा किया है कि मुनीर ने भारत के साथ एक विनाशकारी युद्ध को टाल दिया। ट्रंप ने कहा, मुनीर इस युद्ध को पाकिस्तान की ओर से रोकने में बेहद प्रभावशाली था। यह भी कहा जा रहा है कि मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लंच का निमंत्रण उस समय आया जब उन्होंने ट्रंप को भारत-पाक परमाणु युद्ध को रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने की सिफारिश की। यह भी बताया जा रहा है कि यह लंच मीटिंग पाकिस्तानी-अमेरिकी व्यवसायी साजिद तारार के प्रयासों से आयोजित हुई, जो ट्रंप के लंबे समय से समर्थक और ₹अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप₹ समूह के संस्थापक हैं। तारार पिछले तीन रिपब्लिकन राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ता रहे हैं और उनकी MAGA विचारधारा से करीबी के कारण उनके बेटे को ट्रंप के पहले कार्यकाल में स्टेट डिपार्टमेंट में नियुक्ति मिली थी। रिपोर्टों के मुताबिक तारार ने फोर सीज़न्स होटल में मुनीर के लिए एक सामुदायिक स्वागत समारोह भी आयोजित किया, जिसमें सेना प्रमुख ने प्रवासी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के ₹सच्चे राजदूत₹ बताया और उनके रेमिटेंस, निवेश और उपलब्धियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि में योगदान की सराहना की।

बहरहाल, पाकिस्तान को अपने पहले कार्यकाल में ₹धोखेबाज़₹ और ₹आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह₹ कहने वाले ट्रंप का आतंकी देश के प्रति अचानक यू-टर्न पूरी दुनिया को चौंका रहा है। लेकिन सब यह भी समझ रहे हैं कि अमेरिका इस समय पाकिस्तान का उपयोग करना चाह रहा है। अमेरिका में तो ट्रंप के इन पैंतरों का विश्लेषण भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमैन ने कहा, ₹यह काफी हैरानी वाली बात है कि ट्रंप ने मोदी को चुपचाप व्हाइट हाउस आमंत्रित करने की कोशिश की जब असीम मुनीर भी वहां लंच के लिए मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप को भारत-पाकिस्तान तनावों की पृष्ठभूमि और इतिहास की कोई समझ नहीं है, वह बस एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं ताकि बाद में नोबेल पुरस्कार मिल सके।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

शरणार्थी: दर्द, दृढ़ता और दुनिया से उम्मीद की कहानी [हक़दार सिर्फ़ घर के नहीं, गरिमा के भी हैं वे]

जब रात का सन्नाटा बमों की गड़गड़ाहट में बदल जाए, जब आपके बच्चों की हँसी डर के साये में दब जाए, और जब आपका घर सिर्फ़ एक याद बनकर रह जाए, तब "शरणार्थी" शब्द का वास्तविक अर्थ समझ आता है। यह सिर्फ़ एक शब्द नहीं, बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों का दर्दनाक सच है, जो युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अपनी जड़ों से उखड़कर अनिश्चितता के सागर में भटक रही हैं। 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस, केवल एक तारीख नहीं, बल्कि मानवता के उस ज़ख्म का प्रतीक है, जो तब तक नहीं भरेगा, जब तक हर इंसान को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का हक़ न मिले। यह दिन हमें उन करोड़ों लोगों की पीड़ा, साहस और उम्मीद की कहानियों से जोड़ता है, जिन्हें दुनिया ने "शरणार्थी" का लेबल दे दिया, लेकिन जिनके दिलों में अभी भी अपने परिवार, अपने सपनों और एक बेहतर कल की चाह बाकी है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) के अनुसार, 2025 तक दुनिया भर में 11.4 करोड़ से अधिक लोग जबरन विस्थापित हो चुके हैं। इनमें 3.2 करोड़ शरणार्थी हैं, जो अपने देश की सीमाओं को छोड़कर अन्य देशों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। इसके अलावा, 6.8 करोड़ लोग अपने ही देश में विस्थापित हैं, और लगभग 60 लाख लोग शरण माँगने की प्रक्रिया में हैं। ये आँकड़े केवल संख्याएँ नहीं, बल्कि उन माता-पिताओं की कहानियाँ हैं जो अपने बच्चों को गोद में लेकर युद्धग्रस्त इलाकों से भागे, उन युवाओं की हैं जिनके सपने बमबारी में दफन हो गए, और उन बच्चों की हैं जिन्हें स्कूल की जगह शरणार्थी शिविरों में बड़ा होना पड़ रहा है। सीरिया, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, म्यांमार और यूक्रेन जैसे देशों में चल रहे संघर्षों ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन भी एक नया संकट बनकर उभरा है, जिसने बांग्लादेश, मालदीव और अफ्रीका के कई हिस्सों में लोगों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया है।

विश्व शरणार्थी दिवस की शुरुआत 2001 में यूएनएचसीआर द्वारा की गई थी, ताकि दुनिया का ध्यान उन लोगों की ओर जाए, जिन्हें न चाहते हुए भी अपने घर छोड़ने पड़े। इसका उद्देश्य न केवल इन लोगों के संघर्षों को पहचान देना है, बल्कि उन नीतियों और प्रयासों को बढ़ावा देना भी है, जो उनके जीवन को बेहतर बना सकें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शरणार्थी कोई बोझ नहीं, बल्कि वे लोग हैं जिन्हें परिस्थितियों ने मजबूर किया है। कोई भी जन्म से शरणार्थी नहीं होता; यह एक ऐसी स्थिति है, जो युद्ध, अत्याचार या प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी इंसान पर थोप दी जाती है। फिर भी, समाज में अक्सर उन्हें संदेह की नज़रों से देखा जाता है, उनके इरादों पर सवाल उठाए जाते हैं, और उनकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह मानवता की विफलता का द्योतक है।

दुनियाभर में कई देशों ने शरणार्थियों के प्रति उदारता और मानवता का परिचय दिया है। कनाडा ने 2023 तक 1.5 लाख से अधिक शरणार्थियों को पुनर्वासित किया, जबकि जर्मनी ने सीरियाई और अफगान शरणार्थियों को न केवल आश्रय दिया, बल्कि उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। स्वीडन और युगांडा जैसे देश भी अपनी जनसंख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में शरणार्थियों को अपनाने के लिए जाने जाते हैं। भारत का इतिहास भी शरणार्थियों के प्रति करुणा से भरा है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान 1 करोड़ से अधिक शरणार्थियों को भारत ने शरण दी। तिब्बती समुदाय को धर्मशाला में नया घर मिला, और श्रीलंकाई

तमिलों, अफगानों और रोहिंग्या शरणार्थियों को भी भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद आश्रय प्रदान किया। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत "अतिथि देवो भव" का जीवंत उदाहरण है।

हालांकि, आज वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है। बढ़ता राष्ट्रवाद, आर्थिक संकट और सुरक्षा चिंताएँ शरणार्थियों के प्रति दृष्टिकोण को कठोर कर रही हैं। कई देशों में उन्हें "अवैध प्रवासी" या "खतरा" मानकर सीमाएँ बंद की जा रही हैं। इससे शरणार्थियों का जीवन और कठिन हो गया है। यूएनएचसीआर की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 70% शरणार्थी उन देशों में रहते हैं जो स्वयं आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये देश, जैसे कि तुर्की, कोलंबिया और पाकिस्तान, अपने सीमित संसाधनों के साथ लाखों शरणार्थियों का बोझ उठा रहे हैं। ऐसे में वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वह न केवल आर्थिक सहायता दे, बल्कि शरणार्थियों के पुनर्वास और एकीकरण के लिए दीर्घकालिक नीतियाँ बनाए।

विश्व शरणार्थी दिवस हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि शरणार्थियों की मदद केवल सरकारों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों का काम नहीं है। हम सभी की इसमें भूमिका है। शिक्षण संस्थाएँ शरणार्थी बच्चों को शिक्षा देकर, मीडिया उनकी कहानियों को संवेदनशीलता से उजागर करके, और आम नागरिक छोटे-छोटे प्रयासों जैसे सामुदायिक सहायता या जागरूकता अभियानों के जरिए बदलाव ला सकते हैं। कई शरणार्थियों ने साबित किया है कि अवसर मिलने पर वे समाज के लिए अमूल्य योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन और मैडलिन अलब्राइट जैसे लोग शरणार्थी थे, जिन्होंने नई जमीन पर अपनी प्रतिभा से दुनिया को बदला।

यह दिन केवल शरणार्थियों की पीड़ा को याद करने का नहीं, बल्कि उनके साहस और संभावनाओं को सेलिब्रेट करने का भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हर शरणार्थी के पास एक कहानी है, एक सपना है, और एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानती। हमें उनकी इस ताकत को पहचानना होगा और उन्हें वह सम्मान देना होगा जिसके वे हकदार हैं। जब हम सीमाएँ खींचने और दीवारें खड़ी करने में व्यस्त हैं, तब शरणार्थी हमें याद दिलाते हैं कि मानवता की कोई सीमा नहीं होती। विश्व शरणार्थी दिवस हमें एक मौका देता है कि हम अपने दिलों में उनके लिए जगह बनाएँ, उनकी कहानियों को सुनें, और उनके साथ एक ऐसी दुनिया बनाने का संकल्प लें जो न केवल सुरक्षित हो, बल्कि संवेदनशील भी हो। यदि हम एक भी शरणार्थी के जीवन में उम्मीद की किरण जगा पाए, तो यह इस दिवस की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जब तक हर विस्थापित को "घर" नहीं मिलता, तब तक हमारी मानवता अधूरी रहेगी।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी

राहुल गांधी जुलाई में ओडिशा का दौरा करेंगे, भुवनेश्वर में विशाल रैली करेंगे

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ओडिशा आएंगे। उनका 9 जुलाई को ओडिशा आने का कार्यक्रम है। पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास ने इसकी जानकारी दी है। राहुल के साथ एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ओडिशा आने वाले हैं।राहुल गांधी अपने ओडिशा दौरे के दौरान राजधानी भुवनेश्वर में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे।महिला हिंसा पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य में कानून व्यवस्था की खस्ताहाल स्थिति, महिलाएं असुरक्षित हैं और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। इस बीच, राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास और ओडिशा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लालू समेत अन्य नेताओं ने लिंगराज मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने राहुल गांधी के स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही भक्त चरण दास ने कहा कि अगर वह स्वस्थ और मजबूत रहे तो देश के विकास के लिए और भी संघर्ष करेंगे।

झारखंड में बीते 48 घंटे से जारी वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त, जमशेदपुर में बाढ जैसी हालात

गुमला से ओडिशा का संपर्क टूटा, सरायकेला डीसी ने स्वर्णरेखा का लिया जायजा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, बीते 48 घंटे से जारी तेज वर्षा के कारण समुचे झारखंड का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है . गुमला में पूल धंसने से ओडिशा के साथ संपर्क कटा तो सिंहभूम में घर धंसने से एक महिला की मृत्यु हुई है . बुधवार को सबसे ज्यादा वर्षा सरायकेला खरसावां जिले में हुई थी जबकि बृहस्पतिवार को रांची समेत इस आस पास के जिले में हुई . उधर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने झारखंड के कम से कम 11 जिलों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जतायी है. मौसम विभाग ने गुरुवार 19 जून 2025 को आईएमडी नेशनल फ्लैश फ्लड गाइडेंस बुलेटिन जारी कर कहा कि निचले इलाकों में स्थिति गंभीर होगी. आईएमडी ने कहा है कि झारखंड के 11 जिलों के साथ-साथ उससे सटे ओडिशा के 4 जिलों में भी अचानक बाढ़ आने का खतरा है.

झारखंड के बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में भारी बारिश जारी है . इसकी वजह से कहीं मध्यम तो कहीं भारी बाढ़ आने की आशंका बनी हुई है. सबसे ज्यादा चिंता का विषय निचले इलाके हैं. इसलिए प्रशासन को समय रहते कदम उठाना चाहिए . जिसे देख प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं.

इसी क्रम में आज सरायकेला खरसावां जिला के नये युवा उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह द्वारा चांडिल डैम का जायजा लिया गया . उन्होंने डैम के वर्तमान जलस्तर की जानकारी ली तथा खुले गेटों की स्थिति एवं आसपास के क्षेत्रों में संभावित प्रभाव का जायजा लिया.

उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जलस्तर की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए .इसके साथ ही उपायुक्त सिंह ने निर्देश दिया कि प्रभावित अथवा संभावित रूप से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव के सभी आवश्यक प्रबंध यथाशीघ्र सुनिश्चित किए जाएं. उधर उनके पी ए तथा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सरायकेला अविनाश कुमार राहत व्यवस्था हेतु जनता से संपर्क में हैं .

जमशेदपुर में स्वर्णरेखा एवं खड़काई खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यही नहीं, इनका जल स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है. इससे मानगो, शास्त्री नगर, बागबेड़ा आदि इलाकों में 150 से अधिक मकान डूब गए हैं. राहत कार्य जारी है .स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से 1.20 मीटर ऊपर और खरकई नदी खतरे के निशान से लगभग 3.0 मीटर ऊपर बहने लगी हैं .इन दोनों नदियों के आसपास का इलाका जलमग्न हो गया है. बागबेड़ा, मानगो और शास्त्री नगर में निचले और तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं. वैसे पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन पुरी तरह मुस्तैद है. समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है ।

झारखंड में पेलोल पुल दो टुकड़े में बंटा, वाहनों की लम्बी काफिला जाम

खूंटी -सिमडेगा- ओडिशा संपर्क बाधित, पुलों का यूं टूटना गुणवत्ता पर -?

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची , खूंटी जिला में पेलोल नदी पर बना पुल दो टुकड़ों में बंटकर अलग हो गया है. पुल टूटने के कारण एक ट्रक भी ढलान में फंस गया है. पुल दो हिस्सों में टूटकर नीचे धंस गया है. जिस कारण वहां पर आवागमन बाधित हो गया है.

पुल टूटने से एक गाड़ी टूटे पुल में फंस गई है और आवागमन ठप हो गया है. इस कारण से खूंटी-सिमडेगा मुख्य पथ पर गाड़ियों को लंबी कतार लग गया है. इस घटना की सूचना पर तोरपा पुलिस और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है. वैकल्पिक रास्ते से सिमडेगा की गाड़ियों को भेजने की तैयारी में प्रशासन जुट गया है. बता दें कि पेलोल पूल के टूटने से खूंटी भाया सिमडेगा भाया ओडिशा के साथ संपर्क पूरी तरह टूट गया है.

बता दें कि 29 अगस्त 2022 को 6 करोड़ की लागत से बना गिडुम पुल टूटा था. जिसके कारण जिला में आवागमन बाधित हुआ था. एक बार फिर से पेलोल नदी पर बना पुल के टूटने से आवागमन बाधित हुआ है।

भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान से पक्षी टकराया, 180 यात्रियों की जान बाल-बाल बची

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : इंडिगो की फ्लाइट से पक्षी टकराया, 180 यात्री बाल-बाल बचे। बुधवार दोपहर को भुवनेश्वर बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट से पक्षी टकरा गया। बाद में, गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही इसे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।इंडिगो की फ्लाइट 6717 रनवे से उड़ान भरने ही वाली थी कि तभी विमान के अगले हिस्से पर एक बड़ा पक्षी आकर टकराया। कॉकपिट के सामने लगे शीशे पर खून के छींटे पड़ गए। आगे का शीशा क्षतिग्रस्त होने के कारण पायलट को दोबारा उतरने के लिए एटीसी से अनुमति मांगनी पड़ी। एटीसी द्वारा तुरंत अनुमति दिए जाने के बाद विमान उतरा। नतीजतन, एक बड़ा हादसा टल गया। कुछ ही देर में विमान दोबारा उतरा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। हाल ही में अहमदाबाद-लंदन फ्लाइट हादसे का सार्वजनिक तमाशा हुआ था। विमान में यात्री चिल्लाने लगे। हालांकि, पायलट ने घोषणा की कि कोई बड़ी समस्या नहीं है और यात्री शांत हो गए। इसके बाद विमान पार्किंग एरिया में गया और यात्रियों ने राहत की सांस ली। हालांकि, अहमदाबाद हादसे के बाद भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। रनवे के पास दीवार से सटे जगमारा इलाके में खाने-पीने की दुकान क्यों है। यहां रोजाना दुकानदार कारोबार करते हैं, लेकिन यात्रियों की जान दांव पर लगी रहती है। भुवनेश्वर बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए मुख्य खतरा हवाई अड्डे के पास स्थित मछली और मांस की दुकानें हैं।

हरियाणा पुलिस जातिवादी गुंडो की रखैल बन चुकी है- रजत कल्सन

हरियाणा पुलिस नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति के पीड़ितों को न्याय मिले-रजत कल्सन

हरियाणा पुलिस अनुच्छेद 19 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का कर रही है हनन- रजत कल्सन

हाँसी, 19 जून

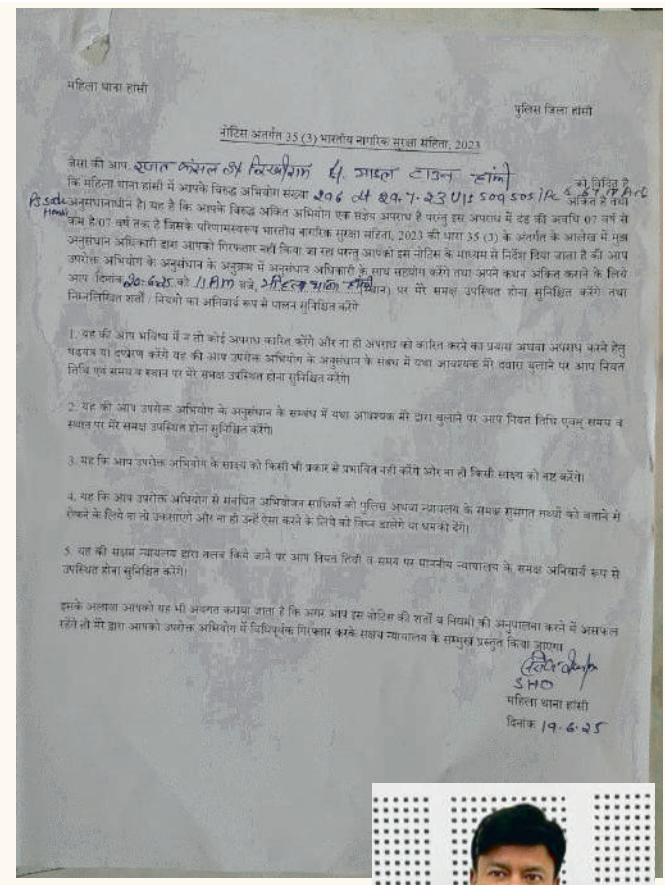

बड़े मजे की बात है, पुलिस हमारे साथ है, यह बात कहते हुए जातिवादी गुंडे हमारे स्वाभिमान को ललकार रहे हैं तो क्या अब हमें संविधान के तहत प्रदत अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार भी नहीं है।

हरियाणा पुलिस ने हाँसी के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए मेरे घर पर रेड की है मेरे परिजनों व छोटे-छोटे बच्चों को भी परेशान किया है। केवल इसलिए ताकि कल प्रस्तावित 20 जून को सुबह 10:00 बजे हमारे धरना प्रदर्शन को रोका जा सके।

हरियाणा पुलिस जातिवादी गुंडो की रखैल बन चुकी है।

लेकिन अब चाहे पुलिस कोई भी गैरकानूनी कार्रवाई करें हम लोग अपने प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।

उन्होंने अनुरोध किया कि सुबह 10:00 बजे हाँसी लघु सचिवालय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे तथा हरियाणा पुलिस की गैर कानूनी व असंवैधानिक कार्रवाई तथा जातिवादी गुंडो की आपराधिक हरकतों को रोकने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें तथा हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाये।

रजत कल्सन दलित अधिकार कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता

शंख भवन में बीजद की अहम बैठक

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : शंख भवन में बीजेडी की अहम बैठक। शंख भवन में पार्टी के वरिष्ठ नेता जुटे हैं। नवीन पटनायक 22 तारीख को इलाज के लिए मुंबई जाएंगे। इस दौरान पीएसी बीजेडी के रोजमर्रा के कामों को देखेगी। देवी मिश्रा को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, नवीन के मुंबई रवाना होने से पहले आज एक अहम बैठक हुई।पूर्व मुख्यमंत्री और बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक इलाज के लिए मुंबई जाएंगे। नवीन को सर्वाइकल अर्थराइटिस की शिकायत है। उनका इलाज 22 तारीख को मुंबई के कोकिलाबेन-धीरूभाई अंबानी अस्पताल में होगा। नवीन ने खुद अपने 'एक्स' हैंडल पर इसकी जानकारी दी है।

पोस्ट में नवीन ने कहा, चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार, मैं इस महीने की 22 तारीख को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में सर्वाइकल अर्थराइटिस का इलाज करवाऊंगा। मेरे निजी चिकित्सक डॉ. रमाकांत पांडा मुंबई में इस इलाज की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और ओडिशा के मेरे भाइयों और बहनों की शुभकामनाओं के साथ, मैं जल्द ही ठीक होकर आप सभी की सेवा करने के लिए वापस आने की उम्मीद करता हूं, नवीन ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर जानकारी दी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail .com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023